● वर्ष-3
● अंक-74
रायपुर, शनिवार
04 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

विक्रांत की लोकप्रियता और संसाधनों के सामने विधायक यशोदा कहीं कमजोर तो नही?

खैरागढ़। विधानसभा चुनाव 2023 में खैरागढ़ जिले के नजरिये से पहला चुनाव माना जा सकता है। खैरागढ़ के विधायक रहते आकस्मिक देवव्रत सिंह के निधन के पश्चात् मध्यावधि चुनाव मे कांग्रेस पार्टी ने यशोदा वर्मा को टिकट देकर खैरागढ़ की सीट जीतने में कामयाबी तो हासिल की पर खैरागढ़ चुनाव लड़ते वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिले की घोषणा करनी पड़ी और जिसे यशोदा वर्मा के विधायक बनते ही पूरा भी किया गया ।जिला बनने के बाद खैरागढ़ छुईखदान का पहला विधानसभा चुनाव है।

खैरागढ़ चुनाव के परिदृश्य को देखने पर यह बात तो स्पष्ट नजर आती है कि जिला बनने के पश्चात जो खुशी खैरागढ़ छुईखदान गंडई के लोगों को होनी चाहिए वैसा कुछ नजर नहीं आता पिछले चुनाव में सत्ता सरकार ने यशोदा वर्मा के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी उससे बात नही बनते देख आनन फानन में जिले की घोषणा करनी पड़ी आज भी कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती यशोदा से लोगों को सत्ता की चकाचौंध वाले चुनाव की उम्मीद थी जो दिख नही रही है पहले और अभी के चुनाव मे फीका पन साफ देखा जा जा सकता है। दूसरी ओर खैरागढ़

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 में भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। विक्रांत सिंह भाजपा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करते रहे है। श्री सिंह के राजनीति की शुरुवात नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में हुई उसके बाद नगर पालिका का अध्यक्ष बना फिर जनपद पंचायत का अध्यक्ष बना उसके बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना विक्रांत खैरागढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे है। उसके विरुद्ध कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा चुनावी मैदान में है। क्षेत्र क्रमांक 73 के मतदाताओं का कहना है कि इस बार विक्रांत सिंह को खैरागढ़ का विधायक बनाना है कही समर्थन कही चुप्पी मतदाताओं मे देखी जा सकती है। भाजपा के छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर विक्रांत के लिए काम कर रहे है।

विक्रांत के 19 साल के राजनीतिक सफर से विधानसभा की जनता खुश है। इस बार खैरागढ़ विधानसभा में विक्रांत और यशोदा के बीच टक्कर है । क्षेत्र वासियों का कहना है कि विक्रांत के विधायक बनने से खैरागढ़ विधानसभा में विकास की कोई कमी नही होगी विक्रांत प्रचार तंत्र और मैनेजमेंट के मामले में भी आगे है ।चुनाव जीतने के लिए पूरी रणनीति के तहत काम कर रहे है। यशोदा वर्मा के प्रति लोगो मे सहानभूति तो है पर आखिर वोटो मे कितना तब्दील होगी ये चुनाव के पश्चात स्पष्ट रूप से समझ आएगा की राजनीतिक पार्टियों के किए जा रहे दावों मे और जनता के मन मे जो है उसके परिणाम ही सब कुछ साफ कर देंगे। बहरहाल चुनाव तो ऐसा होता है की वो करवट किस ओर लेगा इसकी गारंटी कोई नही दे सकता।

सूरजपुर के धान खरीदी केंद्रों पर पसरा सन्नाटा

■ **देर से शुरू हुई बारिश का किसान भुगत रहे खामियाजा**

सूरजपुर। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तब अन्नदाता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सूरजपुर के मेहनतकश किसानों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जिले में एक नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके धान खरीदी केंद्रों पर अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह है मौसम की मार।

सूरजपुर जिले के किसान इन दिनों अपनी फसल को लेकर काफी परेशान हैं। जिले में 1 तारीख से धान खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी शुरु हो चुकी है। लेकिन जिले के किसान धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। वजह है फसल का तैयार नहीं होना। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल देर से तैयार होने के पीछे मौसम की मार है। पूरे जिले में बरसात तब शुरू हुई जब फसल तैयार होने वाली थी। लिहाजा बारिश देर से शुरू हुई तो फसल को जहां नुकसान पहुंचा वहीं फसल भी तैयार होने में देरी हुई। सहकारी समितियों ने जिले में किसानों से धान खरीदी के लिए केंद्र तो बना दिये हैं। लेकिन किसान फसल तैयार नहीं होने के चलते खरीदी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं।

हर साल जहां धान खरीदी का लक्ष्य नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरा कर लिया जाता था वहीं इस बार धान खरीदी का लक्ष्य प्रशासन की पहुंचे से कोसों दूर है। सरकार की ओर से भी लगातार ये कोशिश है कि किसान जल्दी से जल्दी धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचे। पर मौसम की मार का असर धान खरीदी केंद्रों पर पसरे इस सन्नाटे को देख साफ समझा जा सकता है। जिला प्रशासन की मानें तो इस बार 32 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है, और खरीदी के लिए 54 धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं, एक संग्रहण केंद्र भी खरीदी केंद्रों से जमा हुए धान को रखने के लिए बनाया है। पर खरीदी केंद्रों में किसानों के नहीं पहुंचने से हर जगह सन्नाटा पसरा है, यहीं वजह है कि किसानों के माथे पर इस बार चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है।

ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन इन हालातों से वाकिफ नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित केंद्र संचालकों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिससे किसानों की समस्या को न सिर्फ कम किया जा सके बल्कि उनकी फसल को धान खरीदी केंद्रों तक लाने में मदद भी पहुंचाई जाए। पर विभागीय अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि मौसम की बेरुखी और देर से शुरु हुई बारिश के चलते इस बार किसानों की मुसीबत काफी बढ़ गई है।

धरती की सीना चीरकर अन्न उपजाने वाला अन्नदाता आज भी मौसम के सहारे जीने को मजबूर है। कभी सूखा तो कभी बारिश की मार दोनों से किसान जूझता है। पर अब किसान मौसम की लेटलतीफी का भी शिकार होने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस पूरे प्रदेश में बारिश का देर से आना है, और इसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

बस्तर के नक्सल प्रभावित चांदमेटा गांव में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 12 सीटें बस्तर संभाग के अंतर्गत आती हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में मतदान कराना चुनाव आयोग (ईसी) और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। माओवादी संगठन हमेशा से चुनाव का बहिष्कार करता रहा है। तमाम चुनौतियों के बीच इस वर्ष अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। प्रमंडल के 40 अंदरूनी गांवों में कुल 126 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जहां पहली बार मतदान होना है. पहले ये इलाके नक्सलियों के कब्जे में थे. सुरक्षा कारणों एवं जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन गांवों में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गांव से कई किलोमीटर दूर सुरक्षित इलाकों में मतदान केंद्र बनाये गये। दूसरी ओर, नक्सलियों की ओर से ग्रामीणों को आदेश दिया गया कि

जो भी वोट देगा उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण मतदान नहीं कर सके। लेकिन अब हालात बदल गए हैं. पिछले 4 वर्षों में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में 60 से अधिक सुरक्षा बल कैंप स्थापित किए गए हैं। अंदरूनी इलाकों तक भी सड़कें बनाई गई हैं। नक्सलियों का क्षेत्र भी सीमित हो गया है।

मुंडागांव के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मदनलाल नाग ने कहा कि अभी मैं मतदाता पर्चियां बांट रहा हूं। रविवार से मैंने 638 मतदाताओं में से 512 मतदाताओं को घर-घर जाकर पर्चियां बांटी हैं। इस बार ग्रामीण अधिक जागरूक हो गए हैं। पिछले 10-15 वर्षों में। वे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या यह लोकसभा या विधानसभा चुनाव है। इसलिए हम उन्हें बताते हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसलिए उनमें बहुत उत्साह है। पहले लोग वोट देने से झिझकते थे क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। पहली बार 18 साल की उम्र के सभी पुरुष और महिलाएं जो वोट देने के पात्र हैं, उन्होंने आकर अपना नाम दर्ज करवाया है और इस बार पहली बार वोट देंगे।

ईडी टीम आज भी दुर्ग-भिलाई में, 5 नहीं अब तक मिले 7 करोड़ कैश

दुर्ग। गुरुवार को दोपहर भिलाई के हाउसिंग बोर्ड निवासी ड्राइवर असीम दास उर्फ बप्पा बंगाली को रायपुर के ट्राइटेन होटल की पार्किंग में ईडी ने तब धरदबोचा जब वह कोरबा पासिंग कार क्रमांक सीजी-12 एआर-6300 में कैश लेकर भिलाई आने की तैयारी में था। ईडी को उसकी कार से बैग में रखा कैश लगभग 3 करोड़ होटल की पार्किंग में खड़ी कार से मिला। आरोपी चालक असीम दास उर्फ बप्पा को पकड़ जब ईडी ने उसकी निशानदेही पर होटल के एक कमरे में रखे उसके सामान की तलाशी ली तो वहां लगभग 2 करोड़ का कैश और मिला।

ईडी टीम तत्काल आरोपी को पकड़ कैश समेत दफ्तर लेकर आई और यहां पूछताछ में पता लगा कि आरोपी ने एक अन्य कार के माध्यम से रूपयों भरा बैग अपने 14 वर्षीय बेटे प्रीतम दास के मार्फत भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित अपने घर गुरुवार को दोपहर को ही भेजा है। ईडी की एक टीम तत्काल हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भेजी गई लेकिन तब तक आरोपी ड्राइवर की पत्नी और बेटा घर में ताला लगा निकल भागे थे। बंद कमरे का ताला तोड़ जब ईडी भीतर गई तो जिस बेतरतीब ढंग से रूपये रखे गए थे उससे सहज अनुमान लगता है कि रूपयों के कुछ बैग गायब है।

सूत्रों के मुताबिक ईडी को यह भी जानकारी मिली है कि असीम दास के पास लगभग 10 करोड़ रूपये थे जबकि जब्त केवल 7 करोड़ 36 लाख ही हुआ है। बाकी के लगभग पौने 3 करोड़ रूपया कहां गया, यह जांच का विषय है। रायपुर में जब होटल की पार्किंग में ईडी ने असीम को पकड़ा तो कार में प्लास्टिक के दो झोले में 500 रुपए की गड्डियां मिलीं जो कि 3 करोड़ रुपए था।

मोहला मानपुर से संजीव शाह 15 साल बाद चुनाव मैदान में

मोहला-मानपुर। चुनावी राजनीति से करीब 15 साल तक वनवास में रहने के बाद छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी का पूर्व राजपरिवार एक बार फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा है। कांग्रेस और भाजपा ने तीन शाही वंशजों को टिकट दिया है, ऐसे ही एक उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने मैदान में उतारा है।

नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित मोहला-मानपुर (एसटी) से नागवंशी गोंड शाही परिवार के वंशज संजीव शाह भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहला-मानपुर खंड, जो पहले चौकी निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ में 2008 के विधानसभा चुनावों से पहले परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया और तब से भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र में कभी नहीं जीती है।शाह ने कहा, अंबागढ़ चौकी का महल जो अपनी राजनीतिक चमक खो चुका था, एक बार फिर भाजपा के झंडों, पोस्टरों और बैनरों से सज गया है। हम रानी दुर्गावती के वंशजों के करीबी रिश्तेदार हैं। अंबागढ़ चौकी में उनका राजमहल 1740 में बनाया गया था।

हमारा परिवार देश आजाद होने के बाद से ही राजनीति से जुड़ा हुआ था। संजीव शाह की दादी कनक कुमारी देवी 1957 के अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चौकी (एसटी) विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं। 1977 के विधानसभा चुनाव में उनके दादा के छोटे भाई मंझला कुमार के नाम से मशहूर भूपेन्द्र शाह ने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चौकी से जीत हासिल की थी। उनके पिता ने 1980 में भाजपा के समर्थन से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चौकी से चुनाव लड़ा था, लेकिन लगभग 1,000 वोटों से हार गए थे।

अंबागढ़ चौकी राजपरिवार कांग्रेस का करीबी था। भगवा पार्टी ने 1998 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार चौकी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव शाह को मौका दिया। उन्होंने कांग्रेस के गोवर्धन नेताम को हराया। शाह ने 2003 में दूसरी बार सीट जीती जब छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। 2008 में परिसीमन के बाद, चौकी के अधिकांश हिस्से को कवर करते हुए मोहला-मानपुर बनाया गया, जबकि अंबागढ़ चौकी खुज्जी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गई। 2008 में, बीजेपी ने शाह को टिकट देने से इनकार कर दिया और 2008, 2013 और 2018 के चुनावों में अलग-अलग उम्मीदवारों को आजमाया, लेकिन बीजेपी के दो बार राज्य चुनाव जीतने के बावजूद उनमें से कोई भी सफलता का स्वाद नहीं चख सका। बीजेपी ने अब कई सीटों पर अपने पुराने चेहरों की ओर रुख कर लिया है और मोहला-मानपुर उनमें से एक है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सलियों ने 2 वाहनों को किया आग के हवाले

सुकमा। साप्ताहिक बाजार कोंटा से ग्रामीणों को लेकर लौट रही 2 टाटा मैजिक वाहनों को नक्सलियों ने गुरुवार देर रात आग के हवाले कर दिया है। इसकी सूचना पुलिस को आज सुबह दी गई। 7 नवम्बर को प्रथम चरण का मतदान कोंटा विधानसभा में होना है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता और चुनाव बहिष्कार का विरोध तेज होने लगा है। इससे पहले नक्सलियों की ओर से कहीं पर्चा जारी कर तो कहीं आगजनी की वारदातों को अंजाम देकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। उल्लेखनिय है कि बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा है। नक्सलियों की ओर से लगातार चुनाव का बहिष्कार अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है। अब यह देखा जाना होगा कि 7 नवंबर को मतदान कितने शांतिपूर्ण तरीके से कराने में निर्वाचन आयोग सफल होगा।

शिक्षक ने किया कांग्रेस का चुनाव प्रचार, निलंबित

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के अनुमोदन पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने बिल्हा में पदस्थ शिक्षक क्रांति साहू को निलंबित कर दिया है। वहीं फरहदा में पदस्थ उनकी व्याख्याता पत्नी अनिता साहू के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा संचालक स्कूल शिक्षा विभाग से की गई है। कांति साहू शिक्षक एलबी के मूल पद है जो कि वर्तमान में शहरी संकुल स्त्रोत समन्वयक बिल्हा में पदस्थ है। जिला निर्वाचन कार्यालय एवं शिक्षा विभाग को साहू के राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होने की शिकायत मिली थी। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच सहायक संचालक से कराई। जांच में उनकी दल विशेष के पक्ष में लगाव की पुष्टि हुई। यह पाया गया कि साहू ने चुनाव प्रचार करके सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया गया है। जानकारी के अनुसार वह कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहा था। उनकी पत्नी को लेकर भी यही शिकायत है।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकाने

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा सौरभ कुमार ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने आदि बंद रखने के आदेश दिए है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संबंधी कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के निर्देश अनुरुप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री सौरभ कुमार ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोरबा जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर मतदान समाप्ति 17 नवंबर से 48 घंटे पूर्व से अर्थात 15 नवंबर सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकाने, विदेशी मदिरा दुकाने, होटलबार को उक्त शुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए है।

प्रेक्षक जमातिया ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण

कोरबा। निर्वाचन आयोग द्वारा पाली-तानाखार तथा कटघोरा विधानसभा के लिए नियुक्त प्रेक्षक आई.ए.एस. श्री सी.के.जमातिया ने वाणिज्य कर कार्यालय में विधानसभा निर्वाचन हेतु बनाये गये मीडिया अनुप्रमाणन और मीडिया अनुवीक्षण इकाई , वीडियो अवलोकन कक्ष, सी-वीजिल-कंट्रोल रूम आदि का अवलोकन किया। उन्होंने एमसीएमसी इकाई द्वारा प्रतिदिन के अखबारों, टीव्ही चैनलों, सोशल मीडिया एकाउंट में अभ्यर्थियों के प्रचार संबंधी सामाग्रियों के संबंध में प्रभारी अधिकारियों से जानकारी ली और प्रतिदिन के कार्यवाहियों को रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एमसीएमसी के नोडल अधिकारी श्री सेवा राम दीवान संयुक्त कलेक्टर, विनोद सिंह ने एमसीएमसी के कार्यवाहियों को विस्तार से बताया। प्रेक्षक जमातिया ने झगरहा स्थित आई.टी.कालेज में स्थापित किए जा रहे स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूमों में जाकर ईव्हीएम मशीनों और मतदान दलों को वितरित की जाने वाली सामग्रियों की व्यवस्था की जानकारी ली।

बलरामपुर में आर्मी जवान का शव मिलने से सनसनी

बलरामपुर। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जिस जगह लाश पड़ी हुई थी उसके आसपास ढेर सारा खून भी था। सिर पर गंभीर चोट लगी थी। व्यक्ति के हुलिए से ऐसा लग रहा था जैसे वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अज्ञात शव देव कुमार सिंह नाम के व्यक्ति का है। जो आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने गृह ग्राम करमडिहा में आकर रह रहा था और खेती बाड़ी का काम कर रहा था। आर्मी से होने के कारण हर रोज वह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। शुक्रवार को भी सुबह सुबह वॉकिंग करने निकले थे लेकिन इसी दौरान ये हादसा हो गया। बसंतपुर थाना पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना जांच किया जा रहा है। सभी पहलुओं के आधार पर जांच किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

दो दिन में बदल गया नेताजी का मन, निर्दलीय मैदान में कूद कर दी थी चुनौती

कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर बागी बड़े दलों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।कुछ ने निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकी है तो कुछ ने दूसरी पार्टी ज्वाइन करके अपनी दमदारी साबित करने की तैयारी कर ली है। इसी बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले तो टिकट नहीं मिलने से विरोध का झंडा उठाया, लेकिन नामांकन वापसी की तारीख वापस आते-आते अचानक नेताजी का मन बदल गया।ऐसे ही नेता हैं रज्जाक अली। जिनको कोरबा विधानसभा से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन बाद में बी फॉर्म ही नहीं दिया।

बी फॉर्म नहीं मिलने पर रज्जाक ने दी चुनौती

बी फॉर्म नहीं मिलने से रज्जाक ने पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि पार्टी की मजबूरियां होती है। एक कद्दावर नेता ने मेरा फॉर्म रुकवा दिया। लेकिन अब मेरे वजूद की लड़ाई है। गरीब जनता मेरे साथ है, दमदारी के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा।

निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहने वाले रज्जाक अली का अब मन पूरी तरह से बदल चुका है।अब रज्जाक कहते फिर रहे हैं कि जब दो कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे, तब फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए मैंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है।

कोरबा शहर में रज्जाक अली की छवि मनोरंजन करने वाले नेता की है।जो अपनी ओपन जिप्सी में अंधा कानून फिल्म का गाना और म्यूजिक लाउडस्पीकर पर बजाते घूमते हैं। रज्जाक ने शहर में पोस्टर भी लगवाएं थे कि गरीबों का मसीहा आ रहा है। रज्जाक की पत्नी जनपद पंचायत करतला की उपाध्यक्ष हैं। वह खुद भी जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष रहे हैं।इसके अलावा रज्जाक का

नाम आपराधिक मामलों में भी जुड़ा है।इसलिए रज्जाक हवालात की सैर भी कर चुके हैं।

जिला दंडाधिकारी ने रज्जाक को जिलाबदर भी किया है। रज्जाक की फितरत है कि वो हर बार चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार भी कोरबा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। लेकिन सैंकड़ा का आंकड़ा भी ना छू सके।फिलहाल रज्जाक जनता कांग्रेस में थे, लेकिन कोरबा विधानसभा से ही जनता कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया था। स्वर्गीय अजीत जोगी इन्हें नाम से पुकारते थे। कभी पूर्व गृहमंत्री ननकी राम के भी करीबी रज्जाक माने जाते थे। लेकिन अब खुद को कट्टर कांग्रेसी बता रहे हैं।

चुनाव लड़ने से पहले करते हैं नौटंकी

हर बार के चुनाव की तरह रज्जाक ने इस बार भी कई स्वांग रचे।पुलिस से सुरक्षा की मांग की ।इस दौरान रज्जाक ने कहा कि कांग्रेसियों से उन्हें जान का खतरा है। इसके बाद जोगी कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी बना दिया। रामपुर से भी रज्जाक ने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा। लेकिन खुद के साथ और रामपुर से भी नाम वापसी कराई। जनता कांग्रेस ने जब बी फॉर्म नहीं दिया, तब रज्जाक कह रहे थे कि दमदारी से चुनाव लड़ूंगा।

अपनी ही बात पर कायम नहीं रह सके रज्जाक

रज्जाक ने कहा था कि मुझे बी फार्म नहीं मिला तो क्या, गरीबों का साथ है। अगर पार्टी के नेता शेर हैं, तो मैं भी चूहा हूं। चूहे की तरह वोट कतरने का दम रखता हूं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब रज्जाक ने नाम वापस ले लिया और कहा कि कांग्रेसियों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी की है जो समर्थन मूल्य दिया है। उससे ग्रामीण क्षेत्र में जनता मजबूत हुई है। मैं भी सरकार से बहुत प्रभावित हूं। खासतौर पर जयसिंह अग्रवाल जैसा नेता हमने देखा ही नहीं है। इसलिए मैंने उनके समर्थन में ही अपना नाम वापस ले लिया। वह अलग बात है कि पहले मैं विरोध कर रहा था।

चेकिंग के दौरान जब्त किए 3 लाख से ज्यादा नगद

बलरामपुर। जिले के विभिन्न चेकपोस्ट के माध्यम से एसएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए नगद समेत सामान जब्त किया है। टीम ने 3 लाख 91 हजार रुपये नगद समेत 400 कंबल जब्त किया है। एसएसटी टीम द्वारा जिले के धनवार चेक पोस्ट और रामानुजगंज के कन्हर नदी चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। धनवॉर चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम ने 4 लाख 60 हजार रुपये की जीएसटी भी वसूली की है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिसके तहत जिले के विभिन्न चेक पोस्ट में दल के गठन के माध्यम से अवैध रूप से ले जाने वाली सामग्रियों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में धनवार चेक पोस्ट पर जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 15 डीटी 2300 से 1 लाख 30 हजार और दूसरे वाहन क्रमांक डीएल-सीजी 4727 से 2 लाख 61 हजार 500 रुपये जब्त किया गया है। वहीं रामानुजगंज के कनहर चेक पोस्ट से एसएसटी टीम के द्वारा 400 नग कंबल जब्त किया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 36 हजार बताई जा रही है।

● वर्ष-3
● अंक-74
रायपुर, शनिवार
04 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› राजनांदगांव जिले की 4 विस...

दुर्ग में लेंगे चुनावी सभा आज

▪ भाजपा प्रत्याशियों को विजय दिलाने हुंकार भरेंगे मोदी, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था

दुर्ग. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी सभा ले रहे हैं. वे 4 नवंबर को फिर दुर्ग दौरे पर रहेंगे, जहां बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित सभा के माध्यम से पीएम मोदी दुर्ग जिले के छह विधानसभा सीटों एवं दुर्ग संभाग के 20 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को विजय दिलाने की अपील आम जनता से करेंगे. इस सभा की तैयारी के लिए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन, भाजपा कार्यकर्ता जुट गए हैं.

एसपीजी के जवानों ने तारीख का ऐलान होते ही दुर्ग के रवि शंकर स्टेडियम को अपने कब्जे में ले लिया है. आज भिलाई में एसपीजी ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर हेलीपेड से सभा स्थल तक मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था का

जायजा लिया. वहीं अब भिलाई के जयंती स्टेडियम में बने हेलीपैड से लेकर पीएम मोदी की सभा स्थल तक सुरक्षा के चाक चौबन्द व्यवस्था की जा रही है. सीआरपीएफ के जवान एवं बीएसएफ के जवानों को खास तौर पर पीएम मोदी की सुरक्षा में लगाया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को पीएम मोदी के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. पीएम मोदी की सभा में भाजपा नेताओं समेत केंदीय मंत्री मनसुख मंडविया, राष्टीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, डॉ. सरोज पांडेय समेत 20 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहेंगे.

अमित शाह का धमाका, मोदी गारंटी लांच

भाजपा का संकल्प पत्र जारी , सरकार बनते ही 25 दिसंबर को मिलेगा किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च करते हुए बड़े राजनीतिक धमाके किए। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है, वह करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की हैं, वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी। समय सीमा में लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएंगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए घोषणा पत्र को जारी करते हुए विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्धिशाली राज्य बनाने में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एकमुश्त मिलेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसी वर्ष राष्टीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12000 रुपये मिलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 50 फीसदी सब्सिडी के साथ युवाओं को उद्यम के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भाजपा संकल्प पत्र में शामिल प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

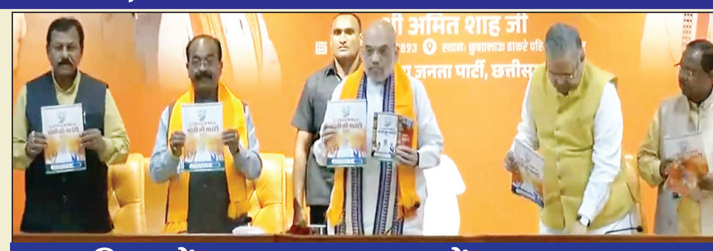

महिलाओं का सम्मान, युवाओं का पूरा ध्यान

कृषक उन्नति योजना - 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी 3100 रुपये में की जाएगी। एकमुश्त भुगतान होगा। पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर खुलेंगे। धान खरीदी से पहले ही बारदाने उपलब्ध होंगे।

महतारी वंदन योजना- प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

सरकारी पदो पर भर्ती - छत्तीसगढ़ के 1 लाख रिक्त शासकीय पदो पर समयबध्द एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित की जाएगी।

आवास - प्रधानमंत्री आवास एवं घर-घर निर्मल जल अभियान के तहत कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने धनराशि का आबंटन होगा और दो सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के हर घर में पीने का शुध्द पानी उपलब्ध होगा।

तेन्दूपत्ता - प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपए प्रतिमानक बोरा दिया जाएगा। संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस देंगे और चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं फिर शुरू की जाएगी।

मजदूर कल्याण - दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आयुष्मान भारत- स्वस्थ छत्तीसगढ़ - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा को दुगुना करके प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देंगे और राज्य में 500 नए जन औषधि केन्द्र स्थापित कर सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराएंगे।

पीएससी - यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ होंगी और राज्य में हुए पीएससी घोटाले की जांच कराई जाएगी।

उद्यम क्रांति - छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

स्टेट कैपिटल रीजन - दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना कर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित एवं संतुलित विकास करेंगे।

इनोवेशन हब - नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

रानी दुर्गावती योजना - रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

500 में सिलेंडर - गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।

विद्यार्थियों को ट्रेवल अलॉवंस- कॉलेज आने जाने के लिए विद्यार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये मासिक अलॉवंस प्रदान करेंगे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग - भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेगी। भ्रष्टाचार शिकायत निवारण व निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन होगा।

सिम्स और सीआईटी - छत्तीसगढ़ के हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) का निर्माण होगा।

महादेव ऐप घोटालाः भूपेश बघेल को दिए 508 करोड़ रुपयेः ईडी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े संकट में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के प्रमोटरों ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपये दिए हैं। ईडी ने कहा कि 5.39 करोड़ रुपये के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में सीएम को पैसा दिए जाने की बात कही है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि सीएम के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वे जांच का विषय हैं।

ईडी ने बृहस्पतिवार को रायपुर में एजेंट असीम दास को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 5.39 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। दावा है कि यह रकम दुबई से चुनावी राज्य में सत्तारूढ़

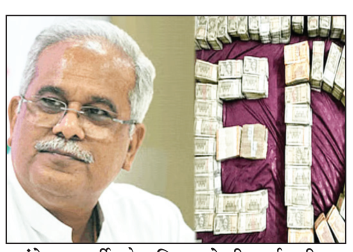

कांग्रेस पार्टी के लिए भेजी गई थी। ईडी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच कर रही है।

ईडी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई रकम को महादेव एप के प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और शुबम सोनी की ओर से भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, महादेव एप के प्रमोटरों की तरफ से अतीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया है और अब तक कुल 508 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मिली थी खुफिया जानकारी

ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि महादेव एप के प्रमोटरों की तरफ से छत्तीसगढ़ में मोटी रकम भेजी गई है। इसके बाद उसने जाल बिछाकर दास को गिरफ्तार किया और उक्त धनराशि बरामद की। दास ने होटल ट्राइटन में खड़ी एसयूवी और भिलाई में एक स्थान पर रकम छिपाकर रखी थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने महादेव एप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है जिनमें 15.59 करोड़ रुपये जमा हैं। जमा धनराशि को पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया है।

जमा धन नेताओं में बांटे गए

ईडी ने पहले कहा था कि महादेव एप के जरिये एकत्र धनराशि रिश्वत के रूप में छत्तीसगढ़ में नेताओं और नौकरशाहों के बीच बांटी गई थी। एजेंसी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को भी भुगतान के तरीके और ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ उनके संबंधों पर पूछताछ के लिए बुलाया था।

दिल्ली दरबार पहुंचा रहे थे बघेलः शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल को प्रीपेड सीएम बताया। उन्होंने राज्य की एक चुनावी रैली में कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के खजाने पर अधिकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है लेकिन बघेल ने छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर दिल्ली में भाई-बहन के चरणों में चढ़ाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्टपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की, जहां उन्होंने मध्य पूर्व के देशों में संघर्ष पर गंभीर चिंता जताई। बातचीत के दौरान दोनों नेता गाजा में सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमत हुए।

प्रमुख समाचार

प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक हैं केजरीवालः गौरव

नईदिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। आज इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर

जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से आम लोगों को खतरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा अगर कोई है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सस्ती राजनीति करना है...हवा में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के प्रयासों की कमी का नतीजा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हवाओं में जो प्रदूषण का कहर है, ये केजरीवाल के निकम्मेपन का कहर है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में है, जिसको सिर्फ रुपया कमाने से मलतब है। उसको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करने से कोई मतलब नहीं है। भाटिया ने कहा कि 3 नवंबर, 2022 एक साल पहले, इसी तरह का प्रदूषण था। केंद्र सरकार पूरी सहायता कर रही थी, पंजाब की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी कि आप ठोस कदम उठाइए प्रदूषण नियंत्रित होगा। लेकिन निकम्मे केजरीवाल और पंजाब सरकार ने वह कदम नहीं उठाया।

जांच से बचने के लिए महुआ मोइत्रा ने किया हंगामाः विनोद

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के गुरुवार दोपहर को लोकसभा आचार समिति की बैठक से बाहर निकलने के एक दिन बाद, उन्होंने समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर

पर अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। सोनकर ने कहा कि मोइत्रा ने जांच के दौरान जवाब देने से बचने के लिए ही हंगामा किया है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा से सिर्फ वही सवाल पूछे गए जिन पर आरोप हैं। उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि जिस प्रश्न का उत्तर वह देना चाहें दे, जिनका वह नहीं चाहती थीं, ना दे। सोनकर ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद वैध सवालों को भटकाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल कर रही थीं और पैनल और अध्यक्ष के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा सांसद ने कहा कि ऐसा करने की बजाय सिर्फ जांच में बाधा उत्पन्न करने के लिए उनके द्वारा यह हंगामा खड़ा किया गया। उन्होंने आचार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वह एक सांसद या महिला को शोभा नहीं देता। वह जवाब देने से बचना चाहती थीं और जांच में बाधाएं पैदा करना चाहती थीं।

कांग्रेस की वजह से राजनीति में विश्वास का संकटःराजनाथ

नईदिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह राजस्थान के राजसमंद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से

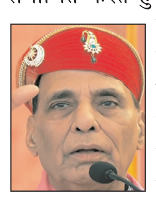

राजनीति में विश्वास का संकट गहराया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने राजनीति में विश्वसनीयता का संकट समाप्त किया है। हमने जो कहा था वह करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नज़दीक आते देख कर राजस्थान की सरकार लोगों को ख़रीदना चाहती है। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौडगढ़ में रतन लाल सोनी, झालावाड में कृष्णा वाल्मिकी, अलवर में हरिश जाटव, योगेश जाटव, चिरंजी लाल सैनी, योगेंद्र जाटव (की भी जिस प्रकार हत्या होती है और जिस तरह माहौल बिगाड़ा जाता है वो राजस्थान की सद्भाव वाली परम्परा को बिगाड़ रही है। भाजपा नेता ने कहा कि जयपुर में एक रोडरेज की घटना पर सम्प्रदाय विशेष के हंगामें के बाद मृतक के परिवार को 50 लाख रूपये, सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ आंवटित किया जाता है।

भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को पीडीए ही हराएगाः अखिलेश

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस से अनबन के बाद समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में

अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। साथ-साथ कहा कि भाजपा का नेतृत्व वाले एनडीए को पीडीए ही हराएगा। अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र बार-बार कर रहे हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो सबसे पहले जातियों की गिनती कराएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि गठबंधन को धोखा देने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। मुझे खबर मिली है कि मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं भाजपा मुख्यमंत्री पद के उतने प्रत्याशियों को लिए घूम रही है।

बिना नाम लिए चीन को आर्मी चीफ का संदेश

नईदिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि भारत का दृष्टिकोण सभी देशों

की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देता है। चाणक्य रक्षा संवाद में एक संबोधन में जनरल पांडे ने यह भी कहा कि भारत दुनिया भर में नए स्थानों पर रक्षा शाखाएं स्थापित कर रहा है और सेना मित्रवत विदेशी साझेदार देशों के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास के दायरे और पैमाने को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। वर्तमान भू-राजनीतिक उथल-पुथल पर चर्चा करते हुए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की बढ़ती महत्ता और कठोर शक्ति की नवीनीकृत मुद्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सेना प्रमुख ने निराशा और भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच भारत को उज्ज्वल स्थान बताया। जनरल पांडेय ने कोई विशेष संदर्भ दिए बिना कहा कि हमारा दृष्टिकोण सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, सभी की समानता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, बल के उपयोग से बचने और अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानूनों और विनियमों के पालन पर जोर देता है।

चुनावों के बाद पार्टी के अंदर भी होंगे बदलाव

प्रणव ढल सामंता

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को 'सेमीफाइनल' बताया जा रहा है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से महज छह महीने पहले हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये लोकसभा चुनाव की संभावनाओं से ज्यादा विभिन्न पार्टियों के आंतरिक समीकरणों को प्रभावित करने वाले हैं। 2018 में बीजेपी सीधे मुकाबले वाले तीन राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़- में कांग्रेस से हार गई थी। लेकिन बमुश्किल छह महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में उसने बाजी पलट दी। तब तीनों राज्यों की कुल 65 लोकसभा सीटों में से उसने 61 पर कब्जा कर लिया था। इसका मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटरों की प्राथमिकता बदल गई थी।

मतदाताओं की प्राथमिकता में इस फर्क की सबसे अच्छी मिसाल ओडिशा में दिखी थी, जहां 2019 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने 146 सीटों वाली विधानसभा में 112 सीटें जीतकर तब लगातार पांचवीं बार सत्ता हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव में 21 में से 12 ही सीटें वह जीत पाई। वहीं, बीजेपी ने 8 सीटें झटक लीं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न देखा जाए तो बीजेडी से बीजेपी की ओर वोटों का करीब 2 फीसदी का शिफ्ट हुआ जबकि दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। इसलिए चुनाव विश्लेषकों का विधानसभा चुनावों के

नतीजों को राष्टीय फलक पर जांचना-परखना तो ठीक है, लेकिन पिछले एक दशक में ऐसी पहल की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी हैं। राष्टीय चुनावों को अब राज्यों के चुनाव नतीजों के कुल योग के तौर पर नहीं देखा जा सकता। राज्यों के चुनाव जरूर वैसे आधार मुहैया कराते हैं, जिन पर पार्टियां खुद को दोबारा खड़ा कर सकती हैं।

नब्बे और दो हजार के दशक में बीजेपी ने खुद को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ हद तक राजस्थान में अपने अच्छे राज्यस्तरीय प्रदर्शनों की बदौलत ही खड़ा किया। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बावजूद इन राज्यों के चुनाव नतीजों ने बीजेपी को मैदान में बनाए रखा। आजकल कांग्रेस अपनी ऐसी ही पुनर्वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। खासकर हिमाचल प्रदेश में पिछले साल और इस साल कर्नाटक में हुई विजय के बाद। जाहिर है, पांच राज्यों के ये चुनाव दोनों दलों के लिए अहम हैं। फिर भी इनका सबसे ज्यादा असर दोनों दलों के क्षत्रपों की भूमिका पर पड़ने वाला है। इसी का दूसरा पहलू है पार्टी में हाईकमान की भूमिका और उसका नियंत्रण।

बीजेपी की बात करें तो वहां मामला उतना उलझा हुआ नहीं है। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की देशव्यापी अपील है जिसका असर न केवल पार्टी के अंदर बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन में भी दिखता है। इसी असर की बदौलत पार्टी पीढ़ीगत बदलाव की तैयारी कर सकी। इसी के तहत कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा और कुछ अन्य नेताओं को विधानसभा चुनाव से कुछ ही पहले हटाया गया। इस तरह का बदलाव कर्नाटक में काम नहीं आया, लेकिन उत्तराखंड और गुजरात में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। वैसे इस बार बीजेपी बड़े बदलाव करने से बचती दिख रही है, लेकिन उसने किसी राज्य में मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। इसका मतलब है कि आगे के हालात बहुत कुछ सीटों की संख्या पर निर्भर करेंगे। स्पष्ट बहुमत की स्थिति में राष्टीय नेतृत्व का जोर बढ़ सकता है, लेकिन जीत-हार का अंतर कम होने पर लोकल लीडरशिप की भूमिका बढ़ जाएगी। हार का अंतर कम होने से मध्य प्रदेश में 2018 में बीजेपी 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद सत्ता पर कब्जा जमा पाई थी। इन इस्तीफों के चलते कई सीटों पर उपचुनाव कराने पड़े, जो बीजेपी के पक्ष में गए। नतीजा यह कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का एक और कार्यकाल मिल गया क्योंकि वह ऐसे इकलौते नेता थे जो सभी गुटों को साथ लेकर चल सकते थे। जाहिर है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे नेताओं के लिए खासे अहम हैं, जिनकी भूमिका इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके पाले में कितने विधायक होते हैं।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वहां आलाकमान को प्रदेश इकाइयों में चल रही गुटबाजी का फायदा मिलता रहा है। राजस्थान में अगर कांग्रेस सरकार चलती रही है तो उसके पीछे अशोक गहलोत की राजनीतिक कुशलता है। लेकिन यह बात भी सही है कि उन्हें लगातार सचिन पायलट पर नजर बनाए रखनी पड़ी जिनकी दिल्ली तक सीधी पहुंच है। मध्य प्रदेश में यह मॉडल उलटा पड़ गया लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चला। वहां टीएस सिंहदेव की मौजूदगी के कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार अंकुश बना रहा।

बांग्लादेश में बढ़ता दखल भारत के लिए गहरी चिंता

बिक्रम उपाध्याय

बांग्लादेश में होने वाला संसदीय चुनाव चीन और अमेरिका दोनों के लिए जोर आजमाइश का खेल बनता जा रहा है। अमेरिका खुलेआम शेख हसीना की सरकार को बार बार यह धमकी दे रहा है कि यदि अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव बिना किसी हिंसा के नहीं हुए तो वाशिंगटन ढाका के लिए अपनी नीतियां कड़ी कर सकता है। अमरीका वीजा से संबंधित चेतावनी पहले ही जारी कर चुका है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को अमरीका आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास ने ढाका में मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह सलाह दी है कि वह विपक्षी दल बीएनपी और जमात ए इस्लामी के साथ बैठक करें और चुनाव के अनुकूल माहौल बनाए। इस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से हालत वहां बिगड़ रहे हैं, उससे इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं बांग्लादेश में मिलिट्री शासन न लागू हो जाए। शेख हसीना अमेरिकी दखल से काफी परेशान हैं। प्रेस कांफ्रेंस करके उन्होंने अमेरिका को जवाब इन कड़े शब्दों में दिया है – वह विपक्ष के साथ तभी बातचीत करेंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बातचीत के लिए बैठेंगे। जाहिर है इन शब्दों में उन्होंने यही संकेत दिया कि अमेरिका उनको कोई निर्देश न दे। इसके आगे हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लोग हत्यारों से कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव होगा और तय समय पर होगा। प्रधानमंत्री ने बीएनपी पर आरोप लगाया है कि यह पार्टी चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने पर तुली हुई है। भारत के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चीन और अमेरिका का बांग्लादेश में दखल यदि आगे और बढ़ता है तो भारत के लिए मूकदर्शक बने रहना संभव नहीं होगा। भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी मुल्क का मामला नहीं है, बल्कि सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश में एक स्वतंत्र किन्तु लिबरल सरकार का होना जरूरी है। यदि यहाँ भी कोई मजहबी और शरिया लागू करने वाली सरकार आती है या फिर कोई मिलिट्री विद्रोह होता है तो वहां रह रहे लगभग डेढ़ करोड़ हिन्दुओं के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में शेख हसीना का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। बीजिंग ने शेख हसीना की सरकार के साथ मिलकर कई परियोजनाएं शुरू की है। बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण (बीडा) के आकड़ों के अनुसार कम से कम 15 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में प्रत्यक्ष निवेश लेकर आई हैं। इसके अलावा, पिछले साल 1.5 अरब डॉलर के एफडीआई प्रस्ताव भी आये थे। बांग्लादेश बैंक के आंकड़े कहते हैं कि देश में चीन से एफडीआई की वार्षिक वृद्धि 13.5त्न रही। 2015 में चीन से प्राप्त निवेश सिर्फ 56 मिलियन डॉलर का था, अब 12 गुना बढ़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका शेख हसीना को लोकतंत्र का दुश्मन बता रहा है। इसी साल सितम्बर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि अपने 14 वर्षों के कार्यकाल में शेख हसीना ने पुलिस, सेना और अदालतों तक पर कब्ज़ा कर लिया है। हर जगह उन्होंने अपने वफादारों को भर दिया है और उन्हें यह बता भी दिया है कि उनके नियमों का पालन न करने के परिणाम क्या होंगे। हसीना ने संस्थाओं का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया है–उनके निशाने पर कलाकार, पत्रकार, कार्यकर्ता और यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ प्रतिशोध का गहरा और व्यक्तिगत अभियान चलाया है। 2023 में बांग्लादेश ने चीन के लिए अपने सभी दरवाजे खोल दिए। दोनों देश के बीच उड़ानें बढ़ रही हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। शी जिनपिंग और शेख हसीना 23 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले थे। वहां जो मुख्य बातें हुई उनमें जिनपिंग का शेख हसीना को यह आश्वासन भी था कि बीजिंग बाहरी हस्तक्षेप से बांग्लादेश को बचाएगा।

पूरी हो गयी सिंगूर की अधूरी कहानी

संजय तिवारी

किसी कम्युनिस्ट शासन में पूंजीवादी विकास की एक ऐसी कहानी जिसे लिखने की शुरुआत 2006 में हुई थी, वो अब जाकर पूरी हुई है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास विभाग को कहा है कि वो टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रूपये ब्याज समेत वापस लौटा दे। इसकी जानकारी खुद टाटा समूह ने 30 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज जारी करके मीडिया को दी है। सिंगूर के संग्राम की जिस पटकथा पर चलकर बंगाल ने ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखा, वह टाटा समूह को आर्थिक क्षतिपूर्ति के साथ पूरा हो गया है।

2000 के दशक में पश्चिम बंगाल के हंसुआ हथौड़ा वाले लाल सलाम समूह को महसूस हुआ कि प्रदेश में बड़े पूंजी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। यह वह समय था जब बुजुर्ग कॉमरेड ज्योति बसु कुर्सी छोड़कर किनारे हो गये थे और बंगाली भद्रलोक से जुड़े पके बालों वाले कॉमरेड साथी बुद्धदेब भट्टाचार्य को बंगाल की सत्ता मिल गयी थी। पूंजीवाद को लेकर बुद्धदेब ज्योति दा की अपेक्षा अधिक उदार थे। उदार तो ज्योति दा भी थे लेकिन उनकी औद्योगिक उदारता का दायरा उनके दामाद को आर्थिक लाभ पहुंचाने से आगे नहीं बढ़ पाया था।

बुद्धदेब बंगाल के औद्योगिक वातावरण में बदलाव चाहते थे। ऐसे में टाटा समूह की ओर से किसी ऐसी कार को बनाने का प्रपोजल मिले जिसकी कीमत एक लाख के आसपास हो तो कॉमरेड के लिए एक पंथ दो काज जैसा अवसर हो गया। पूंजीवाद भी सध गया और जनवाद भी कायम रहा। आखिर उस समय देश के कई राज्य टाटा को जमीन देने के लिए तैयार थे लेकिन जनता की नैनो कार अगर बंगाल के कम्युनिस्ट शासन से बनकर देशभर में जाती तो उसमें जनवाद की अलग ही छवि नजर आती।

लेकिन बुद्धदेब दा से एक चूक हो गयी। उन्होंने टाटा समूह को कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर जिस सिंगूर में जमीन देने का ऐलान किया वह पूरी की पूरी खेती की जमीन थी। जमीन भी थोड़ी नहीं पूरे एक हजार एकड़ दे दी गयी। जमीन के अधिग्रहण का जिम्मा भी बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेडों ने अपने हाथ में ले

लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सिंगूर औद्योगिक निवेश के बजाय राजनीति के खूनी संघर्ष का अखाड़ा बन गया।

किसान तो विरोध में उतरे ही क्योंकि उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया लेकिन वो कामगार भी विरोध में उतर आये जिनकी जीविका इसी जमीन पर निर्भर थी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 6,000 परिवारों के विस्थापन और रोजी रोटी का सवाल था। इसलिए फायरब्रांड नेता ममता बनर्जी को इस मुद्दे में अपने राजनीतिक विकास की पूरी संभावना नजर आयी। मई 2006 में सिंगूर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु हुई और जून-जुलाई से ममता बनर्जी अलग अलग मांगों के साथ मैदान में उतर गयीं। जैसे खेती की जमीन न ली जाए। अगर लिया भी जाए तो हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। जो विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जिनकी जमीन ली जा रही है उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और सबसे बड़ी मांग सीपीएम के पार्टी काडर को इस पूरे प्रकरण से दूर रखा जाए। स्वाभाविक है ये सब कुछ न होना था और न हुआ। विवाद बढ़ा तो पर्दे के पीछे से माओवादी और नक्सलबाड़ी के नक्सली भी किसान मजदूर के हित में लड़ने के लिए पहुंच गये। कहते हैं उस समय नक्सलियों के कमांडर किशन जी ने पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी का साथ दिया। किसान मजदूर का हित साधना हो तो ममता बनर्जी को नक्सली किशन जी की मदद लेने से भी कोई परहेज नहीं था। सिंगूर में झड़पें होती रहीं। राजनीतिक संघर्ष ही नहीं खूनी संघर्ष भी हुए।

बात जितनी बिगड़ती जा रही थी बुद्धदेब की सरकार उतनी सख्त होती जा रही थी। तय हुआ कि भारी पुलिसबल की मौजूदगी में अधिगृहित जमीन की घेरेबंदी की जाएगी। यह काम शुरु भी हुआ भी लेकिन इस काम ने पूरे प्रकरण में आग में घी का काम किया।

सिंगूर में टाटा कार प्रोजेक्ट के विरोध में 4 दिसंबर 2006 को ममता बनर्जी कोलकाता में आमरण अनशन पर बैठ गयीं। उनकी मांग थी कि सरकार तत्काल फेन्सिंग और पुलिस बल दोनों वहां से हटा ले। ममता बनर्जी का आमरण अनशन जैसे जैसे बढ़ता गया उनके प्रति देश भर में राजनीतिक समर्थन भी बढ़ता गया। कुल 25 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं के बहुत समझाने बुझाने पर 29 दिसंबर को खत्म की और तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनका स्वास्थ्य जो गिरा तो फिर पहले वाली स्थिति में कभी नहीं आ पाया। खैर, सितंबर 2008 तक हर पक्ष की ओर से खींचतान चलती रही। सिंगूर से रहस्यमय तरीके से मार दिये किसानों की लाशें मिलती रहीं। इधर यह सब देखकर देशभर के कॉमरेड बुद्धिजीवी एकदम से अपने ही विचारधारा वाली सरकार के खिलाफ हो गये। उन्हें भी लग रहा था कि सिंगूर में साम्यवादी सरकार किसान मजदूर के बजाय टाटा समूह के साथ खड़ी है। सिंगूर में लगातार होती हिंसा और किसानों मजदूरों की रहस्यमयी मौतों को देखकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जनवादी लेखकों, बुद्धिजीवियों, रंगकर्मियों ने जनवादी सरकार का ही विरोध किया, जिसके कारण आखिरकार बुद्धदेव सरकार बैकफुट पर जाने लगी।

ममता बनर्जी ने भी अपना रुख नरम करते हुए कहा कि अगर 400 किसानों की जमीन उन्हें वापस कर दी जाए जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है तो वो भी प्रोजेक्ट का विरोध छोड़ देंगी। तर्क यह भी दिया गया कि टाटा समूह को इतनी जमीन की जरूरत ही नहीं है जितनी उसे दे दी गई है। लेकिन अब तक टाटा समूह और बुद्धदेब सरकार दोनों समझ गये थे अब नैनो कार की फैक्ट्री सिंगूर में नहीं लग पायेगी। सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। शायद साम्यवादी सरकार में किये गये इस पूंजीवादी प्रयोग को लेकर इतने बवाल की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। न टाटा समूह को, न बुद्धदेब को और न ही उन किसानों को जिनकी जमीनें कब्जाई गयी थीं।

आखिरकार फरवरी 2008 में टाटा समूह ने ऐलान किया कि वो बंगाल छोड़कर गुजरात जा रहे हैं। कुछ साल बाद 2011 में बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ तो कम्युनिस्ट शासन भी बंगाल से बाहर चला गया। सिंगूर और नंदीग्राम प्रकरण से हीरो बनकर उभरी ममता बनर्जी राज्य की कुर्सी पर आसीन हो गयीं और आज तक मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के छह महीने के भीतर ही नवंबर 2011 में वो किशन जी भी पुलिस मुठभेड़ में मार दिये गये जो सिंगूर में पर्दे के पीछे से सक्रिय थे। इस तरह संसार से किशन जी भी विदा हो गये।

ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो कानून बनाकर सिंगूर के किसानों की जमीन उन्हें वापस कर दी। देर से ही सही किसानों का भी संघर्ष सफल हुआ। वो भी खुशी खुशी इस पूरे प्रकरण से विदा हो गये। बच गया टाटा जिसका पैसा सिंगूर की जमीन खरीदने में खर्च हुआ था। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उनके पूंजी निवेश को अदा करने का आदेश बंगाल के उसी उद्योग विभाग को दिया है जिसके नाम पर सिंगूर में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। स्वाभाविक है यह पैसा उन्हीं ममता बनर्जी की सरकार टाटा को अदा करेगी जिनकी वजह से टाटा को वहां से आखिरकार बाहर जाना पड़ा था। अब सिंगूर में कोई घाटे में नहीं रहा। सबकी जितनी क्षति हुई उससे अधिक उसकी पूर्ति कर दी गयी। सिंगूर के किसानों को उनकी जमीन और मुआवजा दोनों मिल गया। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की कुर्सी मिल गयी और टाटा समूह को मय सूद ब्याज के उनका पूंजी निवेश वापस मिल गया। इस पूरे प्रकरण में अगर कोई घाटे में रहा तो वह थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी सरकार ने हंसुए को हथौड़े से भिड़ने को मजबूर कर दिया था। बंगाल से कम्युनिस्ट शासन खत्म हुआ तो दिल्ली में उनका दबदबा जाता रहा। उनको जो क्षति हुई उसकी पूर्ति अब शायद कभी न हो। लेकिन राजनीतिक नैरेटिव के लिहाज से पूरी तरह बदल चुके भारत में क्या इस क्षति की पूर्ति कोई करना भी चाहेगा?

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-32)

गतांक से आगे...

उन्हें अतीतकाल में हुई सृष्टि के असंख्य सर्ग दिखाई दिये, इससे समस्त धर्मों एवं गुणों के क्रम उनके स्मृति पटल पर उभर आये। उन्होंने माया से ही विभिन्न प्रकार के आचारों से समन्वित अनेक रूप-रंग की प्रजा को अन्तरिक्ष में गन्धर्वलोक के समान ही संकल्प शक्ति से प्रादुर्भूत कर दिया। उनके धर्म, अर्थ, चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक चित्र-विचित्र शास्त्रों और स्वर्ग-नरकादि की कल्पना (रचना) कर दी।

भुजाओं की तरह तथा मध्य में उदर की तरह समय आने पर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर पूर्ण शरीर के आकार को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि, वीर्य, बल, उत्साह, विज्ञान और वैभव से सम्पन्न हो जाता है। वही शरीर सब लोकों का पितामह भगवान् ब्रह्मा बन जाता है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान के प्रत्यक्ष द्रष्टा भगवान् ब्रह्माजी ने अपनी उत्तम और मनोहर छबि को निहारकर विचार किया कि इस चिन्मात्र आत्मरूपी परमाकाश का कोई आदि अन्त दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? इस प्रकार का विचार करते ही तत्काल उन्हें पवित्र आत्मदृष्टि प्राप्त हुई।

ब्रह्मारूपी मन की कल्पना द्वारा संसार की स्थिति होने से ब्रह्मा के जीवन के साथ इसका (मन का) जीवन है। ब्रह्माजी के आयुष्य समाप्ति के साथ इस मन की भी समाप्ति है। हे द्विजश्रेष्ठ ! वास्तव में न तो कोई कहीं जन्म ही ग्रहण करता है और न अवसान को ही प्राप्त होता है। यह सब मिथ्या है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह प्रपंचात्मक संसार आशारूपी सर्पिणियों की पिटारी है, इसे त्यागना ही उचित है। इसे असत मानकर मातृभाव में स्थिर होना श्रेयस्कर है।

गन्धर्व नगर चाहे सुसज्जित हो या असुसज्जित, वह कैसा भी क्यों न दिखाई दे, वह तुच्छ ही है। उसी तरह अविद्या के अंशरूप ये पुत्र आदि भी प्रपंचरूप हैं, इनके प्रति आसक्ति होना दु:ख का कारण है। धन-स्त्री आदि की वृद्धि के प्रति सुख-दु:ख का भाव रखना निरर्थक है। इसमें सन्तोष मानने की कहीं गुंजायश नहीं। मोह- ह-माया की वृद्धि होने पर इस लोक में कौन सुख-शान्ति का अधिकारी बना है। जिन पदार्थों की बहुतायत से अज्ञानी जन सुख अनुभव करते हैं, उन्हीं से ज्ञानी पुरुष विरक्त रहते हैं।

हे तत्त्वज्ञानी निदाघ ! सांसारिक व्यवहार में जिस-जिसका अभाव होता जाए, उसकी इच्छा न करे और जो-जो सहजता से उपलब्ध हो, उसे स्वीकार करे। अप्राप्त की इच्छा न करना और प्राप्त उपभोग्य सामग्री का उपयोग करना यही पाण्डित्य है। सत् और असत् के बीच शुद्ध पद को जानकर, उसका अवलम्बन ग्रहण कर के बाह्याभ्यन्तरिक दृश्यों को न तो ग्रहण करे और न ही त्यागे। इच्छा और अनिच्छा को समान मानने वाले ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसमें उसी प्रकार लिप्त नहीं होते, जैसे कीचड़ में कमलपत्र पड़ा रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। **क्रमश: ...**

'क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के'

सुरेश कुमार गोयल

4 नवंबर, 1845 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के शिरढोणे में जन्मे वासुदेव के पिता बलवंत तथा मां सरस्वती बाई एक संपन्न और धनी घराने से थे। उनका बचपन कल्याण में बीता। पूना में उन दिनों अखाड़े लगते थे। वासुदेव फड़के प्रात:-सायं अखाड़ों में जाते। कुश्ती के दांव-पेंच सीखते। वह प्रतिदिन 300 दंड-बैठकें निकालते। अखाड़ेबाजी में फड़के के साथी ज्योतिबा फुले थे, जो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध समाज-सुधारक नेता हुए। उनके अलावा वह गोविंद रानाडे से भी काफी प्रभावित थे और उन्होंने नौकरी छोड़ कर युवकों को संगठित किया।

भारत को आजाद करवाने के लिए शहादत देने वालों में तेजस्वी क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के एक ऐसा नाम है, जिन्होंने आरामदायक जीवन त्याग कर अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की और अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया। उनका कहना था, ''भूख से जो लोग मर रहे हैं, उनको मैं कैसे बचा सकता हूं, इस विषय पर अनेक वर्ष मैं सोचता रहा। जिस भूमि का मैं पुत्र हूं, उसी की ये सब संतान हैं। ये लोग अन्नाभाव में भूखे मरते रहें और हम पेट भरते रहें, यह मुझ से देखा नहीं गया। अत: ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मैने सशस्त्र विद्रोह की घोषणा की।''

वासुदेव बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन और सशस्त्र सेना का निर्माण करने वाले भारत के सबसे पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ कर और युवा पत्नी के साथ-साथ नन्ही बालिका का प्रेम भुलाकर ब्रिटिश शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया।

अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को जागृत करने का कार्य वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। महाराष्ट्र की कोली, भील तथा धांगड जातियों को एकत्र कर उन्होंने 'रामोशी' नामक क्रान्तिकारी संगठन खड़ा किया। इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों तथा साहूकारों को लूटा। उन्हें तब विशेष प्रसिद्धि मिली, जब उन्होंने पुणे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। महाराष्ट्र के 7 जिलों में उनकी सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था। 13 मई, 1879 को एक सरकारी भवन में उन्हें लेकर अंग्रेजों की बैठक चल रही थी। वासुदेव फड़के ने साथियों सहित वहां पुहंच कर अंग्रेज अफसरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के सामने अंग्रेजी सरकार थर-थर कांपने लगी और उनकी गिफ्तारी के लिए कई योजनाएं बनीं, लेकिन चतुराई और साहस से वह हर बार उन पर पानी फेर देते। अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकडने़ पर 50 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया किन्तु दूसरे ही दिन मुम्बई में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर 'रिचर्ड' का सिर काटकर लाएगा, उसे 75 हजार रुपए का ईनाम दिया जाएगा। अंग्रेज इससे और भी बौखला गए। पुलिस इनकी तलाश में जगह-जगह छापे मारने लगी। देशद्रोही द्वारा खबर करने पर वासुदेव फड़के 20 जुलाई, 1879 को गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकद्दमा चलाया गया।

वासुदेव की लोकप्रियता से अंग्रेज इतना डरते थे कि उन्हें बंदी बनाए जाने के बाद वहां रखने से विद्रोह न भड़क जाए, इसलिए उन्हें आजन्म कालापानी की सजा सुना दी गई। जनवरी 1880 में वासुदेव बलवंत फड़के अदन पहुंचे। वह अदन जेल से भागने में सफल हुए, पर अदन के रास्ते जानते नहीं थे। उन्हें फिर पकड़ लिया गया। जेल में उन्हें क्षय रोग हो गया और उन्होंने 17 फरवरी, 1883 को अदन की ब्रिटिश जेल में प्राण त्याग दिए। आजादी के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया।

बदलती विश्व व्यवस्था और भारत से अपेक्षा

एम के नारायणन

हम निरंतर तीव्र और बढ़ती भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के समक्ष भारी जोखिम और संभावनाओं के समय में जी रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के आखिर में संशय का शिकार होने के बाद से दुनिया ज्यादा से ज्यादा संघर्ष की तरफ झुकती दिख रही है। नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आज पश्चिमी देशों की कल्पना मात्र रह गई है, दुनिया भर के ज्यादातर देश मात्र इसका दिखावा कर रहे हैं। वर्ष 2022 का यूक्रेन संघर्ष इस गिरावट की शुरुआत है तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष एवं विकास के विस्तार से इसमें तेजी आई है।

जैसे ही दुनिया ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, चीन और उसकी आधिपत्यवादी प्रवृत्ति विशेष रूप से पश्चिम के लिए एक स्थायी चिंता का विषय बन गई और यह मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए भी खतरा है। उनमें से कई देशों के लिए ताइवान ज्वलंत प्रतीक है, जहां कभी भी संघर्ष शुरू हो सकता है। हालांकि ज्यादातर दूसरे देश यह सोचते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला यूक्रेन युद्ध वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, जिसने पहले ही विभिन्न देशों को अपना पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर दिया है।

इस बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसा इसलिए है कि आज इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सैन्य शक्ति और धन मौजूद है। साथ ही विभिन्न तरह के तनावों को झेलने की इसकी क्षमता अनिश्चित बनी हुई है। ताइवान को लेकर संघर्ष या दक्षिण चीन सागर में समुद्री यातायात को लेकर खतरे (जो हमेशा रहने वाला खतरा है) जैसी स्थितियों के नतीजे तब तक गंभीर साबित हो सकते हैं, जब तक कि इससे

उचित तरीके से निपटा नहीं जाता है, क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय शक्तियां और सभी पश्चिमी देश चीन (और रूस एवं उनके सहयोगियों के समूह) के खिलाफ हैं। दोनों पक्षों के पास परमाणु सहित अत्याधुनिक हथियार हैं और ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्या हो सकता है। इस क्षेत्र में शांति चीन के व्यवहार पर निर्भर करती है, लेकिन उसका रवैया अस्पष्ट एवं अनिश्चित है।

शी जिनपिंग के राष्ट्रपति काल में चीन और भी आक्रामक हो गया है, जो पहले एशिया-प्रशांत क्षेत्र में और फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में वर्चस्व हासिल करना चाहता है। चीन द्वारा निर्देशित और चीन के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था के प्रति उसका विश्वास न केवल एशिया के देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आसन्न खतरा है। हाल के घरेलू घटनाक्रम ने भले ही चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी हो, लेकिन वह अब भी विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।

बंटी हुई दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मद्देनजर आज हम पश्चिम एशिया की सबसे शक्तिशाली सेना यानी इस्राइली रक्षा बलों का हाल देख रहे हैं, जिसे हमास ने घातक झटका दिया है, जबकि हमास को कभी बहुत घातक आतंकी संगठन नहीं माना गया। इस्राइल का इस तरह से झुकना एक नए खतरे की आशंका को जन्म देता है यानी कि भविष्य की लड़ाई देश की सेनाओं और आतंकी संगठनों के बीच हो सकती है, जो अप्रत्याशित परिणामों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

शांति का माहौल बनाने के लिए कई महीनों से चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों (इस्राइल और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर सहित) की पृष्ठभूमि में हमास का विगत सात अक्तूबर को किया गया हमला दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक पश्चिम एशिया में शांति की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। हमास के सात अक्तूबर के हमले ने शांति के लिए मौजूद सभी अवसरों और उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया है। खास बात यह है कि इसने न केवल दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, बल्कि आधुनिक संघर्ष को एक नया आयाम दिया है।

हाल के घटनाक्रमनों ने, चाहे वह यूक्रेन हो, पश्चिम एशिया हो या फिर सुदूर पूर्व, निर्णायक रूप से यह प्रदर्शित किया है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन और शांति की दिशा में कोई भी सार्थक कदम उठाने या शांति के लिए बातचीत की शुरुआत करने की उसकी क्षमता पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इसका नतीजा यह है कि जैसे-जैसे 2023 अंत की ओर बढ़ रहा है, दुनिया बिखरी हुई नजर आ रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर असर डालने वाले संघर्षों के समाधान की कोई उम्मीद नहीं है।

इन सबने भारत को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। जी-20 की सफल अध्यक्षता से उत्साहित और अपेक्षाकृत बेहतर अर्थव्यवस्था वाली दुनिया के कुछेक गिने-चुने देशों में से एक भारत से कम से कम यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों में इन विवादों के निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की गई होगी। रूस और अधिकांश यूरोपीय देशों के साथ भारत के बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं और दोनों क्षेत्रों के लोगों एवं नेताओं के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध हैं। हाल ही में यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के सबसे पसंदीदा देशों में से एक बनकर उभरा है। फिर भी यह यूक्रेन-रूस संघर्ष में शांति की उम्मीद जगाने या हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए इस सद्भावना का फायदा उठाने में विफल रहा है। पश्चिम एशिया के संकट में इसकी बहुत कम भूमिका रही है।

कुछ लोग इससे इन्कार करते हुए कह सकते हैं कि आज शायद ही कोई ऐसा देश है, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तेजी से आई मौजूदा गिरावट पर विराम लगाने और संभावित महायुद्ध को रोकने की क्षमता और आवश्यक सद्भावना है, जिस पर दुनिया अभी विचार कर रही है। यदि मौजूदा स्थिति को कुछ और समय तक जारी रहने दिया गया, तो 21वीं सदी को 17वीं और 18वीं सदी की तरह ही देखा जा सकता है। आज भारत के पास अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गिरावट को रोकने के लिए उपयोगी भूमिका निभाने की खातिर मजबूत नेतृत्व और आर्थिक ताकत है, लेकिन उसे जरूरी समय पर सक्रिय होते हुए अपनी क्षमता प्रदर्शित करनी पड़ेगी।

हिन्द स्वराज्य

छुटकारा (भाग-4)

गतांक से आगे...

प्रश्न- राष्ट्र से आप क्या कहेंगे?

उत्तर- राष्ट्र कौन?

प्रश्न- अभी तो आप जिस अर्थ में यह शब्द काम में लेते हैं उसी अर्थवाला राष्ट्र, यानी जो लोग यूरोप की सभ्यता में रंगे हुए हैं, जो स्वराज्य की आवाज उठा रहे हैं।

उत्तर- इस राष्ट्र से मैं कहूँगा कि जिस हिन्दुस्तानी को (स्वराज्य की) सच्ची खुमारी यानी मस्ती चढ़ी होगी, वही अंग्रेजों से ऊपर की बात कह सकेगा और उनके रोब से नहीं दबेगा। सच्ची मस्ती तो उसी को चढ़ सकती है, जो ज्ञानपूर्वक समझ-बूझकर-यह मानता हो कि हिन्द की सभ्यता सबसे अच्छी है और यूरोप की सभ्यता चार दिन की चाँदनी है। वैसे सभ्यताएँ तो आज तक कई हो गयीं और मिट्टी में मिल गयी; आगे भी कई होंगी और मिट्टी में मिल जायेंगी। सच्ची खुमारी उसी को हो सकती है, जो आत्मबल का अनुभव करके शरीर बल से नहीं दबेगा और निडर रहेगा तथा सपने में भी तोपबल का उपयोग करने की बात नहीं सोचेगा। सच्ची खुमारी उसी हिन्दुस्तानी को रहेगी, जो आज की लाचार हालत से बहुत ऊब गया होगा और जिसने पहले से ही जहर का प्याला पी लिया होगा। ऐसा हिन्दुस्तानी अगर एक ही होगा, तो वह भी ऊपर की बात अंग्रेजों से कहेगा और अंग्रेजों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऊपर की माँग-माँग नहीं है, वह हिन्दुस्तानियों के मन की दशा को बताती है। माँगने से कुछ नहीं मिलेगा; वह तो हमें खुद लेना होगा। उसे लेने की हममें ताकत होनी चाहिए। यह ताकत उसी में होगी- 1. जो अंग्रेजी भाषाका उपयोग लाचारीसे ही करेगा। 2. जो वकील होगा तो अपनी वकालत छोड़ देगा और खुद घर में चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा। 3. जो वकील होने के कारण अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ लोगों को समझाने और लोगों की आँखें खोलने में करेगा। 4. जो वकील होकर वादी प्रतिवादी-मुद्दई और मुद्दालह—के झगड़ों में नहीं पड़ेगा, अदालतों को छोड़ देगा और अपने अनुभव से दूसरों को अदालतें छोड़ने के लिए समझायेगा। 5. जो वकील होते हुए भी जैसे वकालत छोड़ेगा वैसे न्यायाधीशपन भी छोड़ेगा। **क्रमश: ...**

भाजपा का विधानसभा ही नहीं लोकसभा चुनाव पर भी ध्यान

नीरज कुमार दुबे

देश में इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। विपक्षी कांग्रेस का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में जीत हासिल कर बढ़त बनाई जाये। अन्य दल भी इन चुनावों में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा सिर्फ विधानसभा चुनावों पर ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों पर भी पूरा ध्यान दे रही है। भाजपा के केंद्रीय नेता दिन में राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं तो शाम को दिल्ली में बैठकें कर लोकसभा चुनावों में जीत की रणनीति बनाते हैं। भाजपा की इन्हीं तैयारियों को देखते हुए ही एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस का पूरा ध्यान विधानसभा चुनावों पर लगा हुआ है जिसके चलते इंडिया गठबंधन का कामकाज ठप पड़ा हुआ है।

जहां तक भाजपा की ओर से लोकसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में की गयी बैठक की बात है तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कई राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और विभिन्न राज्यों के संगठनात्मक नेता उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित थी और इसमें विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हम आपको यह भी बता दें कि यह बैठक कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों द्वारा जाति जनगणना की मांग और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल के बीच हुई है।

बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा हुई और वहां प्रदेश संगठन को इस कार्य में और तेजी से जुटने के लिए निर्देश दिये गये। यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ सहयोगी दलों के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर भी आलाकमान से चर्चा की। बताया यह भी जा रहा है कि योगी सरकार से कुछ मंत्रियों को हटा कर उन्हें संगठन के काम पर लगाया जा सकता है।

बैठक में महाराष्ट्र को लेकर भी काफी लंबा मंथन हुआ। महाराष्ट्र सरकार को अभी कल ही तब राहत मिली जब मराठा आरक्षण आंदोलन दो महीने के लिए स्थगित हो गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में इस मुद्दे पर तो चर्चा हुई ही साथ ही गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी मंथन हुआ। दरअसल, महाराष्ट्र में एनसीपी के एक धड़े के भाजपा के साथ आने के बाद सीटों के बंटवारे का मुद्दा पेचीदा हो गया है क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी लोकसभा चुनावों में अपने लिये उतनी ही सीटें मांग रही है जितनी 2019 में अविभाजित शिवसेना के हिस्से में आई थी। भाजपा भी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है लेकिन नये गठबंधन में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए भी कुछ सीटें छोड़नी ही पड़ेंगी। फिलहाल कोई पक्ष कम सीटों पर मानने के लिए राजी नहीं दिख रहा है।

बिहार के बारे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य के नेताओं के साथ प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गयी और नीतीश सरकार की नाकामियों को जनता के बीच और प्रखरता के साथ ले जाने की रणनीति बनी। बिहार में जातिगत जनगणना मुद्दे तथा इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के होने वाले संभावित बंटवारे से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर भी चर्चा की गयी। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। हम आपको याद दिला दें कि पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस समय हो रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा का जोर राज्य में वापस सत्ता हासिल करने और लोकसभा चुनावों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि बैठक में हरियाणा के नेताओं ने भी शिरकत की। गुरुवार दोपहर हरियाणा के करनाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं को सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। यह लक्ष्य कैसे साकार किया जा सकता है, इसके बारे में भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने राज्य इकाई के नेताओं से चर्चा कर रणनीति बनाई। तेलंगाना के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान भाजपा नेताओं ने विधानसभा चुनावों में अपना प्रदर्शन सुधारने और लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रूपरेखा बनाई।

बहरहाल, हम आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में शामिल हुए राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था और तेलंगाना में भी अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में इन्हीं राज्यों पर भाजपा ने जिस तरह दोबारा से जोर लगाया है वह दर्शाता है कि भाजपा नये क्षेत्रों में जीत हासिल करने पर जोर तो दे रही है लेकिन वर्तमान में अपने पास मौजूद सीटों को भी किसी हालत में नहीं खोना चाहती।

क्या कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में छीन लिए भाजपा के मुद्दे ?

रोहित मिश्र

गाय और राम दो ऐसे विषय हैं जो भाजपा की चुनावी नोटबुक में सबसे ऊपर रहते हैं। हिंदी बेल्ट के राज्यों में गाय और राम कोर मुद्दों के रुप में सामने आते रहे हैं। यह मुद्दे चुनावों को ध्रुवीकृत करने के साथ बीजेपी को वोट दिलवाते रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ के चुनावों में ऐसा नहीं है। राम और गाय यहां मुद्दा तो है लेकिन यह मुद्दा भाजपा की ओर से ना होकर कांग्रेस की ओर से है। आप गाय और राम का नाम कांग्रेस नेताओं के मुंह से सुनेंगे। कांग्रेस की सभाओं में गाय, गौमूत्र और गाय के गोबर की बात होती है। भगवान राम की बात होती है। मां कौशल्या की बात होती है। सवाल यह है कि गाय और राम के यह मुद्दे भूपेश बघेल को चुनावी लाभ दे सकते हैं। बीते पांच सालों में भूपेश बघेल सरकार लगातार गाय और राम पर कुछ न कुछ ऐसा करती रही है कि वह विषय के रुप में जनता के बीच जिंदा रहा। अपने इंटरव्यू में भूपेश यह कहते दिखे हैं कि गाय हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। यह राज्य किसानों का राज्य है जिसमें पशुओं को सम्मान के साथ देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान राम और गौ माता विरासत, संस्कृति और सेवा का विषय है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक बनाया। भूपेश कहते रहे हैं कि गाय की तरह राम भी हमारे लिए राजनीतिक नहीं हैं। मां कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में है। यह राज्य भगवान राम का ननिहाल है। उनके साथ इस राज्य का रिश्ता एक परिवार की तरह है। हम इस पर राजनीति नहीं कर सकते। इसके उलट बीजेपी राम के मुद्दे पर शांत है। उसकी सभाओं में राम और गाय पर बात नहीं होती। ऐसे समय जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है बीजेपी ने इस मसले को चुनावों में नहीं उठाया है। हालांकि अभी बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र नहीं आया है। गौठान और गौमूत्र पर हो सकता है कि बीजेपी के द्वारा भी कोई घोषणा की जाए। बीते पांच सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने गाय और राम के माध्यम से एक साफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की है। इस नए राजनीतिक कोलाज में सरकार ने संस्कृति और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को भी जोड़ा है। राज्य के कई सारे त्योहारों को सरकारी स्तर पर मनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री आंचलिक त्योहारों को मुख्यमंत्री आवास में मनाते हुए दिखे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि धर्म और संस्कृति का यह कोलाज बीजेपी को असहज करता रहा है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिवाकर मुक्तिबोध इसे कांग्रेस की बदली हुई राजनीति के तौर पर देखते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि बाकी राज्यों में राम के नाम से असहज दिखने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बिल्कुल अलग एप्रोच लिया है। वह सारे मुद्दे जो बाकी राज्यों में बीजेपी के वोटरों को धर्म के नाम पर ध्रुवीक्रत करते हैं भूपेश ने उन्हें यहां पनपने नहीं दिया। राम और गाय के अलावा हिंदु देवी-देवताओं के सारे कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता और मंत्री शिरकत करते दिखे हैं। भूपेश सरकार ने राम के साथ एक रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की है। उनकी यह कोशिश कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसी भी तरह का लाभ बीजेपी ना ले पाए। यह चुनावी परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस यह करने में कितनी सफल रही है। राम और गाय कांग्रेस के लिए क्यों जरुरी है इस सवाल पर छत्तीसगढ़ एक समाचार चैनल से जुड़े वरिष्ठ टीवी पत्रकार बरुण सखाजी कहते हैं कि भूपेश सरकार गाय के मामले में सेवा भाव का रुख दिखाया है। प्रदेश में यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है। दूसरी ओर राम के मुद्दे को सरकार ने कामयाबी से अपने पाले में कर लिया है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के माध्यम से वह राम के मुद्दे के साथ जुड़ने में कामयाब रही है। राम के साथ ही साथ सरकार ने रायपुर से 20 किलोमीटर दूर माता कौशल्या के जन्मस्थल को भी विकसित किया है।

चुनावी चंदे में पारदर्शिता की जरूरत

प्रमोद भार्गव

देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी 'महान्यायवादी' आर. वेंकटरमणि ने शीर्ष न्यायालय में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि देश की जनता को राजनीतिक दलों को चंदा कौन देता है, यह जानने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चुनावी बॉन्ड चंदा देने का एक स्वच्छ जरिया है, इसलिए इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। महान्यायवादी ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1-ए) के तहत नागरिकों को चुनावी धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं होने की दलील भी दी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही है। इस मामले में विडंबना यह है कि इसी अदालत के ही 2003 में दिए एक फैसले के अनुसार हर प्रत्याशी को बाध्य किया गया है कि वह अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी शपथ-पत्र में नामांकन देने के साथ दे। साफ है कि मतदाताओं को आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के बारे में जानने का हक तो है, लेकिन दलों के चंदे का स्रोत क्या है, इसे जानने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी ने इस सिलसिले में तर्क दिया है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जानने के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि पार्टियों के वित्तपोषण के बारे में जानने का अधिकार भी है। महान्यायवादी की दलील से साफ है कि सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के हक में नहीं है। वित्त विधेयक-2017 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या कंपनी चेक या ई-पेमेंट के जरिये चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये बियरर चेक की तरह बियरर बॉन्ड होंगे। मसलन इन्हें दल या व्यक्ति चेकों की तरह बैंकों से भुना सकते हैं। चूंकि बॉन्ड केवल ई-ट्रांसफर या चेक से खरीदे जा सकते हैं, इसलिए खरीदने वाले का पता होगा, लेकिन पाने वाले का नाम गोपनीय रहेगा। अर्थशास्त्रियों ने इसे कालेधन को बढ़ावा देने वाला उपाय बताया था, क्योंकि इस प्रावधान में ऐसा लोच है कि कंपनियां इस बॉन्ड को राजनीतिक दलों को देकर फिर से किसी अन्य रूप में वापस ले सकती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर 50 हजार करोड़ रु. से ज्यादा खर्च होते हैं। इस खर्च में बड़ी धनराशि कालाधन और आवारा पूंजी होती है, जो औद्योगिक घरानों और बड़े व्यापारियों से ली जाती है। आर्थिक उदारवाद के बाद यह बीमारी सभी दलों में पनपी है। इस कारण दलों में जनभागीदारी निरंतर घट रही है। कॉरपोरेट फंडिंग ने ग्रास रूट फंडिंग का काम खत्म कर दिया है। इस वजह से दलों में जहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हुआ, वहीं आम आदमी से दूरियां भी बढ़ती गईं।

हिंदुत्व के अखाड़े में भाजपा को कांग्रेस की चुनौती

अंकित सिंह

मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जबकि नतीजे तीन दिसंबर को आएंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में चुनावी वादों की बौछार है। हालांकि, राम मंदिर की भी चर्चा जबरदस्त तरीके से होने लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही इस बात की भी घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। अब इसके बाद कांग्रेस ने अपने नरम हिंदुत्व को मध्य प्रदेश में दिखाना शुरू कर दिया है।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ लगातार नरम हिंदुत्व को लेकर चलते रहते हैं। इसी कड़ी में राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति के बीच एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कमलनाथ ने दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने ही खोला था। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है। यह हमारे पूरे देश और हर नागरिक का है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझ कर इसे हड़पना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसे अपने घर से तो नहीं बनाया है। सरकार के पैसों से बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस श्रीलंका में सीता माता मंदिर बनवाने का अपना वादा निभाएगी। इससे पहले भी कमलनाथ ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा था कि वे राम मंदिर के बारे में ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे की वह उन्हीं का राम मंदिर हो। यह हमारे देश का मंदिर है। यह हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। क्या यह किसी पार्टी का है?

भाजपा) द्वारा अयोध्या में राममंदिर के निर्माण का श्रेय लेने वाले होर्डिंग लगाने पर कांग्रेस द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस चुनावी राज्य में एक वाकयुद्ध छिड़ गया। भाजपा ने कहा कि ''कांग्रेस राममंदिर निर्माण को लेकर दुखी है'', जबकि विपक्षी दल ने उस पर भगवान राम की भक्ति से भटकने का आरोप लगाया। कांग्रेस की इंदौर इकाई ने भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से शिकायत की कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, अयोध्या में राममंदिर और उज्जैन में महाकाल लोक का प्रदर्शन करके धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की शिकायत को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा करते हुए उस पर ''राम विरोधी'' होने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज ने भी पूछा कि कांग्रेस को भगवान राम और राम मंदिर से क्या दिक्कत है। कांग्रेस का कहना है कि भगवान राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्रीराम की कोई पार्टी हो सकती है? जो लोग भक्ति के मार्ग से भटक गए हैं और जिनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान राम के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्रीराम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कमलनाथ ने साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की बीजेपी और ऋस्स के बराबर भूमिका थी... कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करते हैं... अब, हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे। जनवरी में जब राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में जाएं तो उन्हें अपने साथ ले जाएं, राम-श्याम की जोड़ी अच्छी रहेगी।

मध्य प्रदेश में राम मंदिर इस बार बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इसका बड़ा कारण हिंदुत्व का एजेंडा है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान सीता मंदिर बनाने, राम पथ गमन योजना, केवटराज की मूर्ति बनाने, श्राद्ध कर्म में हर हिंदू को फंड मुहैया कराने आदि का वादा करके अपना हिंदुत्व कार्ड तो चल दिया। लेकिन उसका बड़ा दांव बीजेपी को इस मामले को लेकर बैक फुट पर लाना था। इसी के जवाब में भाजपा ने राम मंदिर को ही एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए इसे भुनाना शुरू कर दिया। राम मंदिर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने भाषणों में करने लगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी राम मंदिर को लेकर लगातार बातें कह रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से भी नरम हिंदुत्व का रुख अपनाया जा रहा है। हमने शुरुआत में ही देखा कि कैसे कमलनाथ ने बागेश्वर बाबा को छिंदवाड़ा में बुलाया था। उन्होंने यह भी कह दिया था कि जिस देश में ज्यादा हिंदू है। वहां हिंदू राष्ट्र का सवाल ही नहीं होता। वहीं, कांग्रेस के लिए जब पहली बार प्रियंका प्रचार के लिए जबलपुर पहुंची थीं तब उन्होंने नर्मदा आरती की था।

मध्य प्रदेश में हिंदू वोटरों की तादाद ज्यादा है। यही कारण है कि हिंदुओं को साधने की कोशिश हर पार्टी की ओर से किया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हर पांचवीं सीट पर 3त्र से कम वोटो पर जीत हार का फैसला हुआ था। यही कारण है कि हिंदुत्व वाले दाव को हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती है। यही तो प्रजातंत्र है।

मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों का क्या है हाल?

सिद्धार्थ शंकर गौतम

यूँ तो राजनीतिक दलों के लिए चुनावों में एक-एक सीट और एक-एक वोट महत्त्वपूर्ण होता है और वे इसी हिसाब से प्रत्याशियों का चयन भी करते हैं किंतु चुनाव में कई बार कुछ सीटें प्रत्याशियों के कद अथवा उनके नाम के चलते देश में चर्चा का विषय बन जाती हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ ऐसी ही विधानसभा सीटें हैं जिन पर देश की नजर के साथ ही उन प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा है जो देश की राजनीति में गहरी छाप छोड़ते हैं।

बुधनी में चतुष्कोणीय मुकाबले की चर्चा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस हाईप्रोफाइल विदिशा लोकसभा सीट से सांसद रहे उसी के अंतर्गत आने वाली बुधनी विधानसभा सीट से वे 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे। बाद में 2006, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों में भी वे इसी सीट से जीतते रहे हैं। 2018 में पूर्व मप्र कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए बुधनी से चुनाव लड़ा था किंतु शिवराज सिंह रिकॉर्ड मतों से जीते थे। बुधनी से विपक्ष मज़बूत प्रत्याशी इसलिए उतारता रहा है ताकि शिवराज सिंह को उन्हीं के क्षेत्र में घेरा जा सके ताकि वे क्षेत्र के बाहर प्रचार न कर सकें।

हालांकि अब तक विपक्ष बुधनी में शिवराज सिंह की काट नहीं खोज पाया है किंतु इस बार कांग्रेस और सपा प्रत्याशी के चलते बुधनी में चुनाव दिलचस्प हो गया है। कथित तौर पर राम के नाम पर वोट मानने वाली पार्टी के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस ने टीवी पर आने वाली रामायण में हनुमान का अभिनय करने वाले एक स्थानीय अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दे दिया है। विक्रम मस्ताल ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के घर जाकर उनके परिवार से समर्थन मांगने से करते हुए राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। विक्रम मस्ताल को बुधनी से उतार कर कांग्रेस भाजपा के राम और कमलनाथ के हनुमान के बीच मुक़ाबला चाहती है और विक्रम भी हनुमान के किरदार में ही वोट मांग रहे हैं।

नेता-अभिनेता के लिए मुक़ाबले में असली तड़का तो तब लगा जब अखिलेश यादव की सपा ने विवादित संत मिर्ची बाबा को बुधनी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये वही मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे हैं जिन्हें 2018 में कमलनाथ सरकार ने निगम अध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दिया था। ऑयल मिल के मजदूर से मिर्ची बाबा बनने के क्रम में इनके साथ कई विवाद भी जुड़ते गए। 2019 में मिर्ची बाबा ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह के समर्थन में एलान किया कि यदि दिग्विजय सिंह हारे तो वे जल समाधि ले लेंगे किंतु बाबा अभी जीवित हैं और शिवराज सिंह से पुराने हिसाब चुकता करना चाहते हैं।

मिर्ची बाबा को दिग्विजय सिंह ने स्थापित किया था किंतु 2022 में एक महिला ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और बाबा को 13 महीने जेल में गुज़ारने पड़े। न्यायालय से बरी होने के बाद उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर साथ न देने के आरोप लगाए और विधानसभा चुनाव से पहले वे अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए। हालांकि यह समय ही बताएगा कि हवनकुंड में मिर्च की धूनी देने वाले बाबा की मिर्ची का धुआँ किसकी आँख से पानी लाता है। फिलहाल तो बुधनी में चुनावी चौसर त्रिकोणीय हो चुकी है और परिणाम दिलचस्प होने वाला है।

राष्ट्रीय महासचिव बनाम विधायक

रिकॉर्ड चौथी बार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संभवत: सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केंद्रीय नेतृत्व के चलते उनकी घर वापसी इतनी जल्दी हो जाएगी और वह भी विधानसभा चुनाव में। इंदौर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा इंदौर

4, इंदौर 2 और धार लोकसभा में आने वाली महू विधानसभा को भाजपा का गढ़ बना देने वाले कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस के अमीर प्रत्याशियों में से एक संजय शुक्ला के सामने उतार कर पार्टी इंदौर 1 विधानसभा को भी भाजपा का गढ़ बनाना चाहती है। हालांकि इस क़वायद में उनके पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट जरूर कट गया किंतु वे अपने पिता के लिए इंदौर 1 में युवाओं को एकजुट करने में लगे हैं। 40 वर्ष के राजनीतिक सफर में कोई चुनाव न हारने वाले कैलाश विजयवर्गीय से लड़ने के लिए स्थानीय संजय शुक्ला नेता नहीं, बेटा टैग लाइन से चुनाव प्रचार में उतरे हैं। वे कैलाश विजयवर्गीय को मेहमान भी बताते हैं किंतु इंदौर में महापौर रह चुके कैलाश विजयवर्गीय का क़द और उनके समर्थन में भाजपा के बड़े नेताओं का उतरना उन्हें परेशान कर रहा है और वे अब जातिगत समीकरण के भरोसे हैं जहां ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम गठजोड़ प्रत्याशी की हार-जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इंदौर 1 में चुनाव अब भावनात्मक रूप भी लेता जा रहा है क्योंकि संजय शुक्ला की पत्नी अर्चना शुक्ला ने भी अपना नामांकन जमा किया है जिस पर संजय शुक्ला का कहना है कि भाजपा मेरा नामांकन रद्द करवा सकती है इसलिए मैंने मेरी पत्नी से नामांकन करवाया है। संजय शुक्ला का यह भी कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरे हमनाम संजय शुक्ला का नामांकन जमा होना भाजपा का षड्यंत्र है। संजय शुक्ला जो आरोप लगाएं किंतु कैलाश विजयवर्गीय का चुनावी बिसात में सामना करना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यह कह चुके हैं कि वे मात्र विधायक बनने नहीं आए हैं, वे बड़ी भूमिका में दिखेंगे।

केंद्रीय मंत्रियों के भविष्य का होगा निर्धारण

भाजपा नेतृत्व ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर देश-प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की जिस दिमनी विधानसभा सीट से उतारा है वहाँ 15 वर्षों से कांग्रेस काबिज है। कुल मतदाता संख्या 2 लाख 15 हजार है जिसमें 60,000 से अधिक राजपूत मतदाताओं के चलते नरेंद्र सिंह तोमर की इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2018 के चुनाव के दौरान यहां सर्वाधिक 70 प्रतिशत मतदान हुआ था जो यहां के मतदाताओं की जागरूकता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस ने यहां से वर्तमान विधायक रवींद्र तोमर को उतारा है जिसके चलते राजपूत वोट बंटने का अंदेशा है।

बसपा ने पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया और आप ने सुरेंद्र सिंह तोमर को उतारकर जाति समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। अब चारों प्रत्याशी 30 हजार ब्राह्मण, 48 हजार अनुसूचित जाति तथा 90 हजार अन्य जाति के मतदाताओं को लुभाने में खुद को झोंके हुए हैं। दिमनी विधानसभा चुनाव का परिणाम कई प्रत्याशियों के भविष्य का निर्धारण कर देगा।

इसी प्रकार केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल जिन्होंने 4 विभिन्न सीटों से लोकसभा चुनाव जीता, उन्हें अपने ही छोटे भाई और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल की टिकट काटकर पहली बार विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। नरसिंहपुर को पटेल परिवार का गढ़ माना जाता है और जालम सिंह पटेल ने यहां काम भी बहुत किया है किंतु पटेल परिवार की कथित गुंडागर्दी से क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग नाराज भी है और यही 38 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि लौटे प्रह्लाद सिंह पटेल के विरूद्ध जा रहा है। संसदीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान से कहीं वरिष्ठ प्रह्लाद सिंह पटेल को भाजपा छिंदवाड़ा से कमलनाथ के सामने उतारना चाहती थी किंतु इससे एक ही परिवार के दो व्यक्ति चुनाव लड़ते जिससे भाजपा के खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगता इसलिए जालम सिंह के स्थान पर प्रह्लाद सिंह को टिकट दिया गया। उमा भारती के बाद सबसे बड़े लोधी नेता के रूप में प्रह्लाद सिंह पटेल फिलहाल थोड़ी सुखद स्थिति में हैं।

आदिवासियों के बड़े नेता केंद्रीय राज्य मंत्री फ़ग्गन सिंह कुलस्ते भी अपने गृहक्षेत्र निवास से 1990 के बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। कुलस्ते की डगर इस बार कठिनतम मानी जा रही है क्योंकि जिस मंडला लोकसभा सीट से वे अभी सांसद हैं, उसके चुनाव में उन्हें इसी निवास सीट से सबसे कम वोट प्राप्त हुए थे। यहां कांग्रेस ने वर्तमान विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले को टिकट दिया है।

यह भी कम दिलचस्प नहीं कि 1993 में इसी विधानसभा सीट से हारने पर कुलस्ते ने सांसदी का रूख कर लिया था। निवास विधानसभा का 50 वर्षों का इतिहास रहा है कि यहां से जिस पार्टी का विधायक चुना गया है, प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनी है। अब इस संयोग में फ़ग्गन सिंह कुलस्ते की क़िस्मत क्या होगी, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। अभी तो फ़ग्गन सिंह अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में उतरे हैं जहां उनका मुक़ाबला लोकप्रिय कांग्रेस विधायक से है।

इन सभी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों का परिणाम प्रदेश की राजनीति को बदलकर रख देगा, इतना तय है। ये सभी जीते और भाजपा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन का यक्ष प्रश्न पार्टी नेतृत्व को परेशान करेगा और यदि इनमें से कोई हारा तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर अभी धुंध छाई हुई है।

गरीब, किसान का विकास मोदी को दिखता नहीं, सिर्फ अडानी का विकास दिखता है: बघेल

राम के नाम पर हम वोट नहीं मांगते, कांग्रेस सरकार आई तो 42 लाख लोगों को मिलेगी मुफ़्त बिजली

अभनपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को अभनपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू के लिए चुनाव प्रचार करने अभनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी साहब छत्तीसगढ़ आते है लेकिन उन्हें यहाँ विकास नहीं दिखाई देता है, हमने किसानों की आय बढ़ाई, महिलाओं को रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, गांवों को समृद्ध बनाया, भूमिहीनों को सालाना 7 हजार रुपये की आर्थिक मदद समेत बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, हमने आम आदमी का विकास किया है लेकिन पीएम मोदी जी को गरीबों का विकास नहीं दिखता है उन्हें सिर्फ अडानी का विकास ही दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिनों के वादे को याद करते हुए कहा कि महंगाई कम करने के वादे को लेकर सरकार में आई भाजपा सरकार में महंगाई उफान पर है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोत्तरी से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है लेकिन मोदी सरकार महंगाई रोकने कोई कदम नहीं उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की वापसी होने पर हम गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देंगे।

विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया, हमारी सरकार फिर से आई तो लगभग 42 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस बात से सभा में उपस्थित लोगों ने तालियाँ बजाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग का नारा है राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये लोग भगवान राम के नाम पर वोट और नोट दोनों मांगते है लेकिन हम उनके नाम से वोट नहीं मांगते, राम हमारे आस्था का केंद्र है। हमारी सरकार ने भांचा राम के स्मृति चिन्हों को सहेजने के लिए श्रीराम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से जहां-जहां उनके पग पड़े उन स्थानों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कर रहे है।

15 साल में रमन ने सबको ठगा

राजिम। राजिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमितेष शुक्ला के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किया और वह हैं अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा साथ ही 42 लाख परिवार को बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हांने कहा कि 15 साल में पूर्व मुख्यमंत्री डा। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा हैं लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पांच साल में छत्तीसगढ़ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम माता, राजीव लोचन भगवान, कुलेश्वर महादेव के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल में पूर्व मुख्यमंत्री डा। रमन सिंह ने सबको ठका है क्योंकि उनकी बातों में कोई भरोसा नहीं है। मोदी ने काला धन को वापस लाने, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं किया, उन्हें सिर्फ अडानी का विकास समझ में आता है और वे उन्हीं का विकास कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 16 गारंटी दी है और सरकार दोबारा बनी तो उन्हे भी पूरा करेंगे और आज एक और वादा करता हूं कि 200 यूनिट बिजली पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को फ्री में दिया जाएगा, साथ ही 42 लाख परिवार को बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं होगी।

कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा धर्मांतरण : अमित शाह

कबीरधाम। पंडरिया विधानसभा के ग्राम रणवीरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराया। शाह ने कहा कि कांग्रेस राज में दिन दोगुनी रात चौगुनी धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग कर गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। शाह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर इस रोकने कड़े कानून बनाए जाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन में धार्मिक रूपांतरण बढ़ रहा है। संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है लेकिन छत्तीसगढ़ में गरीब आदिवासियों को धर्मांतरित करने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो राज्य के हित में नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के हर घर और गांव में झड़पें हुई हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। अमित शाह ने कहा हमारी सरकार किसी के धार्मिक मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा देगी तो इसे रोकने के लिए भाजपा की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पंडरिया विधानसभा में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर घोटालों में शामिल होने का भी आरोप लगाया और कहा कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस का प्रीपेड सीएम भी कहा और उन पर राज्य के खजाने को कांग्रेस के एटीएम में बदलने का आरोप लगाया। शाह ने सीएम बघेल पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है।

संक्षिप्त समाचार

दो शराब कारोबारियों के चार ठिकानों पर पहुंची ईडी

रायपुर। झारखंड राज्य में हुए शराब घोटाले के सिलसिले में बुधवार की दोपहर झारखंड से रायपुर पहुंची ईडी की टीम दो शराब कारोबारियों के चार ठिकानों पर जांच के लिए पहुंची। तेलीबांधा इलाके की जीवन विहार कालोनी में शराब कारोबारी अतुल सिन्हा और मुकेश मनचंदा के कार्यालय में ईडी की दस सदस्यीय टीम ने दबिश देकर कई दस्तावेज खंगाले हैं। वहीं टीम के तीन सदस्य गुरुवार को बिलासपुर स्थित डिस्टलरी में जांच के लिए पहुंची है। बताया जाता है कि अगस्त महीने में झारखंड में शराब घोटाले में जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर रायपुर में दो शराब कारोबारियों के यहां छापामार कार्रवाई की गई है। वहां सिलसिलेवार रांची, धनबाद, दुमका, देवघर और गोड्डा स्थित 32 ठिकानों में तलाशी के दौरान घोटाले से संबंधित दस्तावेज मिले थे, इसमें रायपुर के दोनों शराब कारोबारियों की घोटाले में प्रमुख संलिप्तता पाई गई थी। इससे संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद ही छापे मारे गए हैं। ईडी के अधिकारी दोनों कारोबारियों से घंटों पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं।

रायपुर के 4 जगहों में आईटी का छापा

रायपुर। चुनावी मौसम में ईडी और आईटी की सक्रियता पर उठ रहे सवाल के बीच एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग ने रायपुर में छापेमारी की है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दिल्ली टीम ने रायपुर ब्लास्ट के संचालक संजय चौधरी, वॉलफ़ोर्ट ग्रुप के अनिल पारख, सीए अमिताभ अग्रवाल और सीए जौहरी के ठिकानों पर छापा मारा है।

छत्तीसगढ़ के लिए तीन विशेष प्रेक्षक नियुक्त

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए तीन विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के बिहार कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी धर्मेन्द्र एस. गंगवार को छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया है। आयोग ने भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को राज्य के लिए विशेष पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया है। भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 1987 बैच के सेवानिवृत अधिकारी राजेश टूटेजा को विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

आखिर क्यों बागी हो गए अजीत कुकरेजा?

■ **सावित्री जगत व हिम्मत भाई पटेल भी जातिगत वोट प्रभावित करेंगे**

रायपुर। आखिरकार नहीं माने अजीत कुकरेजा। कौन है अजीत कुकरेजा बताने की जरूरत नहीं। रायपुर उत्तर विधानसभा से टिकट के दावेदार कांग्रेस से थे। वरिष्ठ पार्षद एमआईसी मेंबर्स कांग्रेस परिवार से नाता,सिंधी बिरादरी का प्रतिनिधित्व जैसे कई कारणों को लेकर वे जिस दिन से नामांकन दाखिल किए थे चर्चा में आ गए। जिस अंदाज में वे भीड़ लेकर पहुंचे थे सबके कान खड़े हो गए थे। फिर भी चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री बघेल के कहने पर वे नाम वापस ले लेंगे लेकिन नहीं लिया। अब यह भी चर्चा हो रही है कि क्या उनसे

बात नहीं की गई या वे अपनी जिद्द पर अड़ गए। आखिर क्यों बागी हुए कुकरेजा के सवाल पर यह जानकारी आ रही है कि पहले वे महापौर की दौड़ में शामिल थे लेकिन ढेबर को बना दिया गया। इसे लेकर कई मौकों पर वे नाराजगी जाहिर करते रहे। इस बार युवाओं को टिकट देने की बात आई तो उत्तर विधानसभा से उन्होने दावा ठोका। लेकिन कांग्रेस ने फिर अपने पुराने विधायक को मैदान में उतार दिया। जातिगत बाहुल्यता को देखते हुए तब जबकि इस बिरादरी से किसी को भी न तो कांग्रेस और न ही भाजपा ने टिकट दी है माना जा रहा था कि समाज की नाराजगी दूर करने उन्हे टिकट दी जा सकती है वे लगातार दिल्ली की दौड़ लगाते रहे लेकिन नहीं मिली और कुकरेजा ने निर्दलीय चुनाव लडना तय कर लिया। अब पार्टी से निकाला जाना तो तय है।

बड़ा सवाल चुनाव में कितना असर डाल पायेंगे।।? निश्चित रूप से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचायेंगे। जातिगत समीकरण के लिहाज से देखें तो इनकी एकजुटता में भीतरखाने से भाजपा के नाराज लोगों का भी समर्थन मिल सकता है। संसाधन में कोई कमी नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक समितियों का बड़ा समूह इनके साथ जुड़ा हुआ है जिनका वे लगातार सहयोग करते रहे हैं। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के बावूजद राजनीति और चुनाव है आगे क्या कुछ हो सकता है दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि अब इस सीट पर जीत हार का समीकरण प्रभावित तो होगा।

इस सीट के साथ एक और बड़ी बात यह भी है कि भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रही उत्कल समाज की सावित्री जगत भाजपा का वोट काट सकती है। वही सकल गुजराती समाज ने हिम्मत भाई पटेल को निर्दलीय उतारा है मतलब जातिगत फैक्टर यहां जमकर चलेगा और दावेदारों को अपने वोट को सहेजने में पसीना छूट जायेगा।

रायगढ़ से 4 एवं लैलूंगा से 1 अभ्यर्थी ने किया नाम वापसी

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के अंतर्गत नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों में से आज दो विधानसभा से कुल 5 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ से 4 अभ्यर्थी संतोष कुमार साहू, राजीव रत्न गुप्ता, गोपाल प्रसाद दुबे एवं संजय शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से अशोक कुमार भगत ने नाम वापस लिया है। रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों में अब कुल 42 प्रत्याशी विधानसभा निर्वाचन-2023 में शामिल होंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से 8 प्रत्याशियों में मनीषा गोंड (जनता कांग्रेस), विद्यावती सिदार (कांग्रेस), सुनीति सत्यानंद राठिया (भाजपा), अजय कुमार पंकज (हमर राज पार्टी), रघुवीर राठिया (गोंडवाना गणतंत्र पार्टी), श्रवण भगत (बहुजन मुक्ति पार्टी), भजन सिदार (निर्दलीय) एवं महेन्द्र कुमार सिदार (निर्दलीय) शामिल है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया से 8 प्रत्याशियों में उमेश पटेल (कांग्रेस), परिमल यादव (जोगी कांग्रेस), आम आदमी पार्टी से प्रवीण विजय जायसवाल, महेश साहू (भाजपा), भवानी सिंह सिदार (हमर राज पार्टी), यशवंत निषाद (जोहार पार्टी), गोवर्धन राठिया (निर्दलीय) एवं विनोद चन्द्र सिंह राठौर (निर्दलीय) शामिल है।

पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में

■ **40.78 लाख से अधिक मतदाता करेंगे अपने वोटिंग का इस्तेमाल**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए पहले चरण में 7 नवम्बर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इनमें से दस विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे सात बजे से दोपहर तीन बजे तक तथा दस विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में मतदान वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में राज्य के कुल 40 लाख 78 हजार 681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19 लाख 93 हजार 937 पुरुष मतदाता, 20 लाख 84 हजार 675 महिला मतदाता तथा 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में कुल 5304 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे।

विधानसभा आम निर्वाचन के लिए पहले चरण में 7 नवम्बर को पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में प्रथम चरण में मतदान वाले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13, भानुप्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8 , कोंटा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10, राजनांदगांव में 29, डोंगरगांव में 12, खुज्जी में 10, मोहला-मानपुर में 9, कवर्धा में 16 तथा पंडरिया में 14 अभ्यर्थी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं।

द्वितीय चरण की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 958 अभ्यर्थी होंगे चुनाव मैदान में

■ **द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए मतदान तिथि 17 नवंबर को**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद अब 958 अभ्यर्थी ही निर्वाचन के लिए मतदाताओं के बीच जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए आज नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 108 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 14 अभ्यर्थियों ने नाम वापसी की। उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद कुल 1066 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए थे, जबकि द्वितीय चरण में नामांकन के अंतिम दिन 30 अक्टूबर तक कुल 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था।

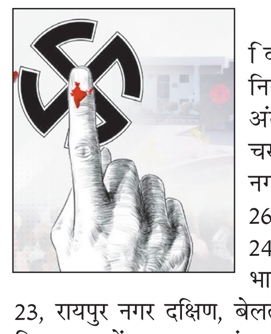

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर नगर पश्चिम में 26, दुर्ग शहर में 24, बिल्हा, भाटापारा में 23-23, रायपुर नगर दक्षिण, बेलतरा में 22-22, बिलासपुर में 21, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कसडोल में 20-20, रायगढ़, कोरबा में 19-19, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, बेमेतरा में 18-18, भटगांव, लोरमी में 17-17, सीतापुर, पाटन, वैशाली नगर में 16-16, कोटा, मुंगेली, अकलतरा, जैजैपुर, खल्लारी, कुरूद में 15-15, कटघोरा, तखतपुर, सक्ती, रायपुर नगर उत्तर, संजारी बालोद, दुर्ग ग्रामीण, साजा, नवागढ़ में 14-14, प्रतापपुर, सामरी, अम्बिकापुर, मस्तुरी, अभनपुर, भिलाई नगर, गुण्डरदेही, में 13-13, प्रेमनगर, लुण्ड्रा, धमतरी में 12-12, रामानुजगंज, जशपुर, कुनकुरी, पामगढ़, बलौदाबाजार, आंरग, राजिम में 11-11, मरवाही, बसना, अहिवारा में 10-10, भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़, रामपुर, पालीतानाखार, चन्द्रपुर, बिलाईगढ़ में 9-9, बैकुण्ठपुर, पत्थलगांव, लैलुंगा, खरसिया, सरायपाली में 8-8, धरमजयगढ़, सिहावा में 7-7, बिन्द्रानवागढ़ में 6, डौण्डीलोहारा में 4 अभ्यर्थी शेष बचे है।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर को कुल एक करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 81 लाख 41 हजार 624 पुरुष मतदाता और 81 लाख 72 हजार 171 महिला मतदाता तथा 684 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण

ललित कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जिला राजनांदगांव है, जहां से कुल 90 सीटों में से 4 विधानसभा और एक लोकसभा सीट आती हैं। इनमें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी विधानसभा शामिल हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। शुरू से ही वीआईपी जिले के रूप में प्रसिद्ध राजनांदगांव इसलिए और प्रमुख हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक बीजेपी सरकार में सीएम रहे डॉ. रमन सिंह का यह विधानसभा क्षेत्र है। यह जिला संस्कारधानी होने के साथ ही पत्रकाकरिता जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी राजनांदगांव जिला महत्वपूर्ण सियासी स्थान रखता था। राजनांदगांव जिले का क्षेत्रफल 8022.55 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही जिले का साक्षरता प्रतिशत 78.46 है। जिले में 4 ब्लॉक राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया और डोंगरगढ़ आते हैं।

राजनांदगांव जिले का जातीय समीकरण

इस जिले में पिछड़ा वर्ग में साहू समाज की अच्छी खासी आबादी है। यही मतदाता हार जीत का आंकड़ा तय में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जिसमें साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। इसके साथ ही सामान्य वर्ग की भी आबादी अच्छी खासी है। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियां ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती हैं। समाज से जुड़े लोगों को देखते हुए रणनीति तैयार करती हैं, जिसका सीधा फायदा प्रत्याशी को मिलता है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर आबादी शहरी है। इस कारण शहरी क्षेत्र में पार्टियों का फोकस रहता है। इस विधानसभा सीट में एक बड़ी आबादी ओबीसी की है इसलिए ओबीसी वोटर्स को साधने का काम राजनीतिक पार्टियां करने में लगी हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां सामान्य,ओबीसी फैक्टर हावी है। यही जीत तय करते हैं।

राजनांदगांव जिले में स्थानीय मुद्दे

स्थानीय मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदान मतदाता इस बार भी मतदान करेंगे। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी यहां प्रमुख रहेंगे। जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा शासनकाल में हुए कई निर्माण कार्य जो कि अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जिले में युवाओं को रोजगार देने के लिए एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उद्योगों की स्थापना और युवाओं को रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी। राजनांदगांव विधानसभा में भी रोजगार और उद्योगों की स्थापना सहित अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण करना ही

इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसको लेकर जनता वोट करेगी। इस बार भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आएगी।

राजनांदगांव- इस सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 211407 है, जिसमें पुरुष 103705, महिला 107700 और थर्ड जेंडर 2 मतदाता 2 हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस विधानसभा सीट से लगातार तीन बार से विधायक हैं। 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट पर कब्जा किया। इस कारण इस सीट में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। कांग्रेस भी इस को जीतने लगातार प्रयास कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी की भांजी करुणा शुक्ला कांग्रेस से राजनांदगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी थीं और रमन सिंह को कड़ी टक्कर दी थीं। पूर्व मुख्यमंत्री महज 17000 वोटों के अंतर से ही जीत पाए थे। इस बार भी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में है। राजनांदगांव विधानसभा सीट बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी और किसान नेता गिरीश देवांगन नए चेहरे हैं। वो एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वहीं कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती हुई दिख रही है।

डोंगरगढ़- इस सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी विनोद खांडेकर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता स्वामी बघेल चुनाव लड़ रही हैं। खांडेकर 2003 में पहली बार विधायक बने थे। वहीं हर्षिता वर्तमान में राजनांदगांव जिला पंचायत सदस्य हैं। यहां कुल मतदाता 209648 हैं, जिसमें पुरुष 105600 , महिला 104044 और ट्रांस जेंडर 4 हैं। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। साल 2018 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के भुनेश्वर बघेल ने बाजी मारी थी। उनके मुकाबले में भाजपा की तरफ से सरोजनी बंजारे को टिकट दिया गया था। कांग्रेस चुनावी लड़ाई को एकतरफा बनाते हुए 35 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। भाजपा को महज 51 हजार वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 86 हजार से अधिक वोट मिले थे।

डोंगरगांव- इस सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी भरतलाल वर्मा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी दिलेश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं। भरतलाल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वे वर्तमान में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं दिलेश्वर साहू दूसरी बार के विधायक हैं। यहां कुल मतदाता 202631 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 101976 महिला 100655 और ट्रांस जेंडर 0 हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पर वर्चस्व रहा है। पिछले दो विधानसभा चुनावों से कांग्रेस प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कमर कस ली है और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। साल 2018 में कांग्रेस के दिलेश्वर साहू को 84,581 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के मधुसूदन यादव को 65498 ही मत मिल थे।

खुज्जी- इस सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी गीता घासी साहू के सामने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू चुनाव लड़ रहे हैं। गीता साहू पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं भोलाराम 2008 में विधायक रह चुके हैं और 2019 में सांसदी का चुनाव लड़े थे पर हार गए। खुज्जी विधानसभा में कुल मतदाता 191267 हैं, जिसमें पुरुष 95042, महिला मतदाता 96228 है। खुज्जी विधानसभा सीट कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है। पिछले तीन चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं। इस वजह से ये कांग्रेस की महत्वपूर्ण सीट है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस की छन्नी साहू विधायक हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रदूषण से भी ज्यादा दिल्ली के लिए खतरनाक हैं केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। आज इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से आम लोगों को खतरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा अगर कोई है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सस्ती राजनीति करना है...हवा में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के प्रयासों की कमी का नतीजा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हवाओं में जो प्रदूषण का कहर है, ये केजरीवाल के निकम्मेपन का कहर है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में है, जिसको सिर्फ रुपया कमाने से मतलब है। उसको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करने से कोई मतलब नहीं है। भाटिया ने कहा कि 3 नवंबर, 2022 एक साल पहले, इसी तरह का प्रदूषण था। केंद्र सरकार पूरी सहायता कर रही थी, पंजाब की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी कि आप ठोस कदम उठाए, प्रदूषण नियंत्रित होगा। लेकिन निकम्मे केजरीवाल और पंजाब सरकार ने वह कदम नहीं उठाया।

उपराष्ट्रपति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगे राघव चड्ढा

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर प्रवर समिति के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा के सभापति 'आप' विधायक की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आगे का रास्ता तलाशने का प्रयास करेंगे। कोर्ट ने 'आप' सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की, अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले संबंधी आगे के घटनाक्रम से उसे अवगत कराने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीद जताई कि उपराष्ट्रपति इस पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे।

तेलंगाना में वाईएसआर का कांग्रेस को समर्थन का ऐलान

हैदराबाद। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने आज कहा कि वह तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और इसके बजाय उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन सुश्री शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में वोटों के विभाजन से बचने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही है, जिससे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। बीआरएस की आसन्न हार की पटकथा लिखने में, यह महसूस किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका है, और इस स्तर पर सत्ता विरोधी वोटों का कोई भी विभाजन केसीआर को पद से हटाने में बाधा बनेगा। शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी ने राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के भ्रष्ट और जनविरोधी शासन को समाप्त करने के लिए बलिदान देने का फैसला किया है।

तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

नईदिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी और इसे तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, चुनाव के लिए नामांकन दायर करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर तक इन्हें हर कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 11 बजे से दिन में तीन बजे तक स्वीकार किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 13 नवंबर को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि के भीतर उम्मीदवार के काफिले में केवल तीन वाहनों को जाने की अनुमति है, जबकि आरओ के कमरे के अंदर, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्तियों को जाने की अनुमति है।

मैं निर्दोष हूं, ममता व अभिषेक सब जानते है : ज्योतिप्रिय

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में ईडी की गिरफ्त में आए वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने बीजेपी पर फिर से फंसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, वह पार्टी के साथ हैं। बालू के नाम से मशहूर पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी और पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जानते थे कि वह निर्दोष हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह ज्योतिप्रिय को मेडिकल जांच के लिए ईडी कार्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कमांड अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, मैं साजिश का शिकार हूं। बीजेपी ने मुझे फंसाया है। ज्योतिप्रिय मल्लिक ने यह भी दावा किया कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। ज्योतिप्रिय ने दावा किया कि भाजपा और राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें फंसाया है।

छत्तीसगढ़ के अभनपुर में नरेंद्र मोदी पर भड़के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रधानमंत्री गाली देने और झूठ बोलने का कारखाना चला रहे : खड़गे

अभनपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभनपुर में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ 30 परसेंट टका का प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक में भी भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 40 परसेंट का प्रचार किया जिसे हमने उखाड़ फेंक दिया।खड़गे ने कहा कि देश में इतनी गंदी चल रही है। मणिपुर में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन एक दिन भी मोदी जी ने वहां जाकर उन्हें शांत कराना मुनासिफ नहीं समझा। क्या ऐसे देश चलाएंगे। मोदी अपने दोस्त अडानी, अंबानी की मदद करते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में एसटी एससी परेशान हैं। मोदी को गरीबों की कोई चिंता नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई को बार बार भेज रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है डटकर मुकाबला करेंगे। यहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी इन सबसे डरने वाली नहीं है। हमारी पार्टी 125 साल पार्टी है। हमने जेल जाकर इस देश को बचाया है। भाजपा आरएसएस के नेता क्या कभी जेल गए।

मोदी ने खोली गाली और झूठ की फैक्ट्री

भाजपा का कहना है कि 70 साल में कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया। हमने 70 साल में काम किया इस वजह से आप पीएम बने। हमने लोकतंत्र की रक्षा की। आपने क्या किया। पहले भाजपा भी कांग्रेस के नेता जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ की। लेकिन आज भाजपा सुबह उठते ही सिर्फ गाली देने का काम करती हैं। मोदी जी ने गाली देने और झूठ बोलने का कारखाना खोला है।

देश की जनता से किया झूठा वादा

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2014 में मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार देश में आने पर बाहर से काला धन लाकर देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपये डालेंगे।

तो फिर झूठ कौन बोल रहा है। या तो पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं या फिर देश की जनता झूठ बोल रही हैं। 2 करोड़ नौकरियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कहती हैं कि मोदी झूठों की सरकार हैं। ऐसी बात करने वाले नेहरू, और गांधी फैमिली पर हमेशा टिप्पणी करते हैं। भाजपा का यही काम है जहां जहां कांग्रेस विपक्ष में होती है वहां उन्हें परेशान किया जाता है। जो पैसा जनता का है कांग्रेस का है उसे केंद्र देने में परेशान करती है। ये क्या उनकी जागीर है ये हमारा हक है जिसे देने में भाजपा को परेशानी होती है।

कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्री ओबीसी

खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं वो बैकवर्ड से हैं। वो ऐसा बोलकर लोगों को अपनी गरीबी का अहसास दिलाते हैं। खड़गे ने सवाल किया कि क्या भूपेश बघेल अपर कास्ट वाले हैं? खड़गे ने कहा कि एक बैकवर्ड क्लास का आदमी ही गरीबों का दर्द जानता है। हमारे पास बैकवर्ड क्लास के शख्स चीफ मिनिस्टर हैं। मोदी बैकवर्ड के नाम पर रोते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, कर्नाटक में सीएम, राजस्थान के सीएम भी ओबीसी है। कांग्रेस ने लोगों के लिए काम की है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस जब केंद्र में थी तब भी हम गांव गरीबों के लिए काम किया। हमारी वजह से ही देश के लोग यहां तक पहुंचे। तुम तो कल परसो आएं हो। 70 साल में कांग्रेस ने ही विकास किया है। देश में जो बड़े बड़े अस्पताल देख रहे हो वो सब कांग्रेस ने किया है। तुमने 9 साल में क्या किया। तुम सिर्फ घूमते रहते हो, देश के लिए क्या कर रहे हो। जो कुछ नहीं किया वो हमसे पूछ रहे है कि क्या काम किया।

कांग्रेस के कारण ही पीएम बने मोदी

मोदी ने 9 साल में क्या किया, लोगों को बताएं। मोदी सिर्फ घूमते रहते हैं। मोदी ने खुद कुछ नहीं किया लेकिन कांग्रेस को कोसते हैं। 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं करती तो मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते और शाह होम मिनिस्टर नहीं बनते। कांग्रेस ने देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाया है। जिस स्कूल में अमित शाह ने पढ़ाई की है, वो भी कांग्रेस ने बनाया है।

गुजरात में 13 साल में मुख्यमंत्री रहे क्या किया, छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस ने कितना काम किया। खड़गे ने कहा कि जनता ऐसे आदमी के बहकावे में ना आए, एक बैकवर्ड क्लास का आदमी ही पिछड़े वर्ग का दर्द जानता है। छत्तीसगढ़ के कका पास के कका है। पीएम मोदी दूरदर्शन है जो दूर से ही दर्शन देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दूर ही रखना है।

अगर हमारी सेंट्रल गवर्मेंट आई तो बैकवर्ड क्लास सेंसस लगाएंगे। उसकी जांच कर जनगणना की जाएगी। ताकि पिछड़े वर्ग के गरीबों को उसका फायदा मिले। हमारा दूध पीकर हमने जो खाद्य संग्रह किया वो खाकर हमसे सवाल कर रहे हैं। हमारे जल जंगल जमीन को बचाना है इसलिए गरीबों की पार्टी को बनाकर देश को बचाना है। खड़गे ने एक बार फिर मोदी को दूर दर्शन वाला बताया। खड़गे ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना जरुरी है।

मध्यप्रदेश में भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना

मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा विकास : जेपी नड्डा

भोपाल। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा ने राज्य में अपना प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रीवा के त्योंथर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं, जो झूठे वादे करके, गुमराह करके, आपको छलावे में डालकर वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं, जो पांच साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड देकर बताते हैं कि हमने आपके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि 20 साल से कांग्रेस की सरकार महिला आरक्षण बिल पर बैठी हुई थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में नारीशक्ति वंदन विधेयक दो दिन के अंदर पास हो गया। अब महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित होंगी।

नड्डा ने कहा कि पहले सरकारें आती थीं और वह सरकारें जनता की सरकारें नहीं होती थीं। वह किसी जाति की, वर्ग की, परिवार की सरकार होती थी। ऐसी सरकारें सिर्फ अपना सोचती थीं, समाज का नहीं सोचती थीं। लेकिन मोदी जी के आने बाद गांव, गरीब, शोषित, पड़ित, दलित, वंचित, युवा, महिला, किसान सभी को ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि जो सरकार आपके अधिकार के 2 लाख मकान वापस कर दे, जल जीवन मिशन का 248 करोड़ रुपया वापस कर दे। ऐसी निकम्मी सरकार को मध्य प्रदेश में वापस नहीं आने देना है। उन्होंने लोगों से पूछा कि कांग्रेस के समय में आपको क्या मिला?

इसके जवाब में नड्डा ने कहा कि आपको कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, 2जी घोटाला मिला। एक तरफ घोटालों की सरकार कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा भारत है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। ये मैं नहीं कह

रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि भारत में अब अत्यधिक गरीबी 1% से भी कम है। भाजपा 2003 से मध्य प्रदेश में सत्ता में है, दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक की 15 महीने की अवधि को छोड़कर जब कमल नाथ ने कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था।

मोदी आज मप्र के दौरे पर

भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी प्रचार का रंग अब चढ़ने लगा है। सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस ने वोटरों को साधने के लिए नया प्लान तैयार किया है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा करते हुए नज़र आएंगे। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में शनिवार से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम 8 दिनों में 14 जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय स्तर के नेता और स्टार प्रचारक किसी न किसी विधानसभा सीटों पर रात्रि विश्राम करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ, विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रैलियों के अलावा पदयात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। अभियान की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष खरगे दो रैली करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मुकाबला आज

बेंगलुरु। आईसीसी विश्व कप 2023 में अंक तालिका समीकरण उलझ गया है। एकमात्र भारतीय टीम ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आईसीसी के अनुसार बांग्लादेश की टीम विश्व कप से बाहर है। तीन सीट के लिए 8 टीम में मुकाबला है। 10 टीम विश्व कप में भाग ले रही हैं। मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आईसीसी विश्व कप 2023 के अपने अगले मैच में एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का 35वां मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबले की मेजबानी करेगा। आईसीसी विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड का नेतृत्व टॉम लैथम कर रहे हैं। टूर्नामेंट में बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ने टूर्नामेंट में अब तक 7-7 मैच खेले हैं। 4 जीत और 3 हार के साथ ब्लैककैप्स के खाते में 8 अंक हैं। पाकिस्तान के 7 में से 3 मैच जीतने और 4 मैच हारने के बाद 6 अंक हैं। जहां पाकिस्तान ने अपना पिछला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जीता था, वहीं न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार गया था।

न्यूज़ीलैंड- केन विलियमसन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन, मैट हैनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, विल यंग, काइल जैमीसन।

पाकिस्तान- बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमां, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 283 अंक चढ़ा निफ्टी 19,200 के पार

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव रुझानों और बॉन्ड यील्ड में जारी नरमी के कारण हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुए। आज दोनों फंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने से बॉन्ड यील्ड में नरमी आई है। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 283 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 97 अंक की बढ़त दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमशः 0.71 प्रतिशत और 0.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 282.88 अंक यानी 0.44% फीसदी की बढ़त के साथ 64,363 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 64,535 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 64,275 तक आया।

एमआरएफ का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में 351% बढ़ा

नईदिल्ली। टायर निर्माता एमआरएफ ने शुक्रवार 3 नवंबर 2023 को अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 351.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 586.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 129.86 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही 24 में 588.75 करोड़ रुपये की तुलना में मुनाफा 0.35 प्रतिशत कम था। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर ऑपरेशन से रेवेन्यू 6.70 प्रतिशत बढ़कर 6,217.10 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 5,826.30 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर, ऑपरेशन से रेवेन्यू 3.46 प्रतिशत कम था। पहली तिमाही 24 में यह 6,440.29 करोड़ रुपये रहा था।

डिफेंस और ईवी पार्ट्स भी बनाएगा रेमंड समूह

नईदिल्ली। रेमंड समूह ने अपने मौजूदा इंजीनियरिंग कारोबार को और मजबूत करने के लिए 682 करोड़ रुपये में मैनी प्रिसिजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 59.25 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। रेमंड लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि मैनी प्रिसिजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एमपीपीएल) की एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन तथा रक्षा क्षेत्र में उपस्थिति है। अधिग्रहण को नकद तथा आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कंपनी के अनुसार, ''यह अधिग्रहण एक पूरक व्यवसाय के साथ रेमंड के मौजूदा इंजीनियरिंग व्यवसाय को और मजबूत करने का रणनीतिक कदम है, जिसकी एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तथा रक्षा के उभरते क्षेत्रों में पहले ही उपस्थिति है।'' यह अधिग्रहण जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (जेके फाइल्स) की अनुषंगी कंपनी रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड (आरपीएएल) के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।

देश में कोयला उत्पादन अक्टूबर में 18.59% बढ़ा

नईदिल्ली। भारत में अक्टूबर में कोयला उत्पादन 18.59 प्रतिशत बढ़कर 7.86 करोड़ टन रहा। देश में पिछले साल समान अवधि में कोयला उत्पादन 6.63 करोड़ टन रहा था। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनी सीआईएल का कोयला उत्पादन इस साल अक्टूबर में 15.36 प्रतिशत बढ़कर 6.10 करोड़ टन रहा, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 5.29 करोड़ टन था। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-अक्टूबर में उत्पादन बढ़कर 50.70 करोड़ टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में यह 44.84 करोड़ टन था। अक्टूबर में कोयले की आपूर्ति बढ़कर 7.93 करोड़ टन हो गई, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 6.71 करोड़ टन थी।

तेल की कीमतों में उछाल क्या महंगाई करेगी बेहाल?

अनिल तिवारी

इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का असर अब दुनिया भर में दिखने लगा है। इस जंग से भारत की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इजराइल-हमास युद्ध के कारण कच्चे तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के चलते तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर की ओर जा रही हैं, वहीं वैश्विक खाद्यान्न संकट के मद्देनजर खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका भी गहरा रही है। हालांकि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में थोक एवं खुदरा महंगाई के सूचकांक, महंगाई में कमी का संकेत दे रहे हैं लेकिन चुनौती पूर्ण वैश्विक भू-राजनीतिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के दौर में महंगाई के बढ़ने की आशंका अधिक है।

मालूम हो कि युद्ध के चलते तेल उत्पादक देशों द्वारा की जा रही कटौती के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति घटने और उसकी कीमतों के ऊपर जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें इस साल लगभग 28% तक बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड वायदा 94 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिसके युद्ध न रुकने की स्थिति में जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल होने की बात कही जा रही है। तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं।

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 10.02 प्रतिशत बढ़ी जिसके कारण पेट्रोल में 13.4%, डीजल में 12% और एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल में 47% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आने से आयातित कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता बढ़कर 87.8 प्रतिशत हो गई

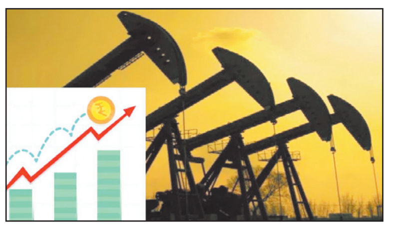

है। रियायती रूसी आपूर्ति के बावजूद हमारा वार्षिक कच्चे तेल का आयात 158 बिलियन डॉलर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% ज्यादा है। मात्रा के लिहाज से कच्चे तेल का आयात 9.4% बढ़कर 232.4 मिलियन मिट्रिक टन हो गया। पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में 4.8% की वृद्धि हुई,और उनके आयात में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन निर्यात में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

इजराइल हमास के बीच जारी जंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है क्योंकि युद्ध के चलते महंगाई बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया तो कच्चे तेल की आपूर्ति अवश्य बाधित होगी जिसके कारण तेल की कीमतों में और अधिक तेजी आएगी। भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है रोजमर्रा की चीजों में महंगाई का बढ़ना। चूंकि महंगाई मध्यम वर्ग को अधिक प्रभावित करती है, इसलिए अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई को बांधे रखना सरकार के लिए एक कठिन चुनौती की तरह है। पिछले दिनों विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी महंगाई के बढ़ने की चुनौती प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है। पूर्व में प्रस्तुत महंगाई के अनुमान से नया अनुमान अधिक बताया गया है। सितंबर महीने में रासायनिक उत्पादों, खनिज, तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जुलाई 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, वह अगस्त 2023 में घटकर 6.8 प्रतिशत और सितंबर में 5.02 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह कमी अनाज, सब्जी, परिधान, फुटवियर, आवास एवं सेवाओं की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हुई है। बीते 6 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। महंगाई को लेकर चुनौतियां लगातार बड़ी हो रही हैं। पिछले माह ज्यादातर समय कच्चे तेल का दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर रहा, अब यह और बढ़कर 94 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है।

किसने दस्तक दी है, दिल पर कौन है.....

छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में करीब आधा दर्जन सीडी,एसएमएस कांड हो चुके हैं।इसमें कई राजनेता जुड़े रहे हैं,हालांकि जितनी भी सीडी की जांच हुई है उसमें किसी को दोषी नहीं पाया गया।सन 2002 में कांग्रेस सरकार के एक राज्य मंत्री रहे नेता की अश्लील सीडी सुर्खियों में रही हालांकि यह सार्वजनिक नहीं हुई पर इस सीडी को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही। 2003 में विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के कद्दावर नेता,तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की सीडी भी चर्चा में रही। किसी होटल में उनका स्टिंगऑपरेशन किया गया। उसमें जूदेव का एक डॉयलॉग..%पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं...को भी प्रमुख समाचार चैनलों में दिखाया गयाऔर बाद में जूदेव को अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा साथ ही उनका छग के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का दावा भी स्वमेव समाप्त हो गया।इस सीडी की भी जांच हुई पर मामला सिफर ही रहा।इसी के साथ 2003 में ही डॉ. रमन सिंह की पहली सरकार बनने के समय भाजपा विधायकों की खरीद-फरोख्त का भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था पर इस मामले में भी कोई प्रगति नहीं हुई। 2005 में संसद में सवाल पूछने के नाम पर पैसा लेने के मामले में स्टिंगऑपरेशन में राजनांदगांव के तत्कालीन सांसद प्रदीप गांधी को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। एक भाजपा नेत्री का एसएमएस भी काफी चर्चा में रहा।इधर 2008 में जग्गी हत्या कांड के मामले में फैसला आने के बाद दोषी करार दिये एक आरोपी के भाई ने भी एक सीडी जारी की थी जिसमें मुख्यआरोपी पर लेन-देन का आरोप लगाकर बरी करने का जिक्र था। इस सीडी को लेकर अवमानना याचिका भी लगी। इधर 2013 में इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की सीडी भी जारी हुई।इसमें तब के सत्तापक्ष के कुछ बड़े नेताओं के नाम थे।अंतागढ़ उपचुनाव 2013 में कांग्रेस ने 2016 में एक सीडी जारी की थी जिसमें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी से चुनाव नहीं लड़ने के एवज में सौदेबाजी करने का जिक्र था। जिसमें एक युवा नेता तथा एक नेता के दामाद का भी जिक्र था। वहीं डॉ रमनसिंह के एक मंत्री की भी एक सीडी की भी बड़ी चर्चा हुई,कुछ पर मामले बनें,गिरफ्तारी भी हुई पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया।वैसे शुक्र है कि इस विधानसभा चुनाव मेंअभी तक किसी सीडी की चर्चा नहीं है पर कुछ सीडियां आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा.....?

चाचा की लड़ाई दो भतीजों से इस बार....

छ्ग विधानसभा चुनाव में सबसे हाईप्रोफ़ाइल सीट पाटन तो थी ही पर अब इस सीट में चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहां परंपरागत प्रतिद्वंदी चाचा भूपेश बघेल तथा भतीजे विजय बघेल के बीच तो मुकाबला होना तय है। पर नामांकन दाखिले के अंतिम दिन दूसरे भतीजे(?) अमित अजीत जोगी की इंट्री से चुनाव दिलचस्प हो गया है। भूपेश बघेल के कांग्रेस अध्यक्ष रहते ही अजीत जोगी,डॉ रेणु जोगी सहित अमित जोगी को कांग्रेस से न केवल बाहर होना पड़ा बल्कि नई राजनीतिक पार्टी भी बनाना पड़ा.. वैसे इसी के बाद छ्ग में कांग्रेस की सरकार भी बनी और भूपेश सीएम भी बने।जोगी परिवार से भूपेश की राजनीतिक और व्यक्तिगत कटुता किसी से छिपी नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि जोगी कॉंग्रेस के कॉंग्रेस में विलय नहीं होने के पीछे भूपेश बघेल की अहम भूमिका है। वे किसी भी हालत में अमित जोगी की कांग्रेस में वापसी के विरोधी हैं।वैसे इस विधानसभा चुनाव में अमित जोगी अपनी तथा अपनी पार्टी के लिये अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहे हैं...?

अमीर विधायक्-पहले सिंहदेव, दूसरे अमितेष शुक्ला ...

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 447.77 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर विधायक हैं।वहीं राजिम विधायक अमितेष श्यामा चरण शुक्ला 74 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनके बाद अकलतरा के भाजपा विधायक सौरभ सिंह ठाकुर हैं,जिनकी संपत्ति 27 करोड़ रुपये है।पाटन का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएम दाऊ भूपेश बघेल की कुल संपत्ति 23 करोड़ रुपये है और राज्य में 15 सालों तक सीएम रहे भाजपा नेता रमन सिंह ने 10 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की है।

पूर्व आईएएस ओपी चौधरी की पत्नी के खिलाफ शिकायत...

विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग सहित छ्ग चुनाव आयोग को शिकायत कर कलेक्टर को हटवाने में सफल होनेवाले पूर्व आईएएस तथा रायगढ़ के भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी की पत्नी तथा रेल अधिकारी चुनाव आयोग की जाँच के दायरे में है।

कांग्रेस ने रायगढ से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी की पत्नी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है।कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से ओपी चौधरी की पत्नी पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है।यहां यह बताना जरुरी है कि ओपी चौधरी की पत्नी रेलवे में अधिकारी है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता और सिविल सेवा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है।

और अब बस....

- छ्ग में पहली बार एक महिला आईएएस रीना बाबा कंगले विस चुनाव करा रही हैं।
- अजातशत्रु बृजमोहन अग्रवाल इस बार कड़े मुकाबले में फंसे हैं।
- कोटा विधानसभा में इस बार रेणु जोगी,प्रबल प्रताप,अटल श्रीवास्तव और निर्दलीय तरुण साहू के बीच दिलचस्प मुकाबला है?

सीएम योगी का छत्तीसगढ़ दौरा, 9 विस क्षेत्रों में करेगें सभा

रायपुर । छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा। वहीं चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े -बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 9 विस क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो करेंगे। सुबह 10.30 योगी आदित्यनाथ रायपुर पहुंचेंगे। वहां से अंतागढ़ में आमसभा को संबोधित करेंगे। 12.10 बजे अंतागढ़ से रवाना होकर डोंगरगांव जाएंगे। डोंगरगांव में आमसभा में चुनावी हुंकार भरेंगे। फिर दोपहर 2 बजे योगी आदित्यनाथ पंडरिया जाएंगे। दोपहर 3 बजे पंडरिया से कवर्धा रवाना होंगे। 3.30 बजे कवर्धा में रोड शो करेंगे। कवर्धा से शाम 5.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायपुर एयरपोर्ट लौटेंगे। शाम 6 बजे बिरगांव में सभा और रोड शो करेंगे। रात 8 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में योगी आदित्यनाथ आराम करेंगे। 5 नवंबर को बीजापुर, बस्तर, भाटापारा और राजनांदगांव में प्रचार करेंगे।

मोदी की गारंटी कांग्रेस की तरह झूठा घोषणा पत्र नही: मूणत

रायपुर। रायपुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं ऊंचे ऊंचे राजनीतिक भाषणों और वादों से दीगर वे जनता से सीधे मुखातिब होकर जनसमस्याओं का संकलन कर उसके निदान हेतु प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं जहां एक ओर उनके सतत प्रतिद्वंदि उन पर जुबानी तीर चलाने में मशगूल हैं वहीं राजेश मूणत का कहना है की मैने कभी राजनीतिक स्तर गिरा कर जनसेवा का भाव नहीं अपनाया मैने सदैव जनसेवा को प्रमुखता से अपनाया और उसके निदान के लिए लगातार कार्य किया और मैं ही नही भाजपा का हर प्रत्याशी भाजपा की विचारधारा को जानता के बीच पोषित करने में विश्वास रखता है भाजपा ने जब जब जनता के बीच जाकर वादे किए उन्हें अक्षरसह पूरा किया चाहे बात धारा 370 की हो , राम मंदिर निर्माण की हो , या हर गरीब के सर पर पक्की छत की हो हमने जनता से जो वादे किए उसे अक्षरसह पूर्ण किया ।

महादेव एप का सीधा संबंध बघेल से ईडी ने जारी की प्रेस रिलीज: डॉ. रमन

रायपुर। आज ईडी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर महादेव एप घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे 508 करोड़ के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजा जब चोर हो जाता है तो जुएँ-सट्टे वालों से भी ?508 करोड़ का कमीशन खाने लगता है। छत्तीसगढ़ की तिजोरी में ड़ाका डाला वो क्या कम था कि प्रदेश के युवाओं को जुएँ-सट्टे की लत लगाने वालों से अपना हिस्सा भी बटोरने लगे दाऊ भूपेश बघेल? अब समझ आया कि आप श्वष्ठ से इतना क्यों डरते थे क्योंकि आप सिर्फ अपराधियों के संरक्षक नहीं बल्कि खुद में इस जुर्म में शामिल रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल को पकड़े जाने का डर पहले से था इसलिए ईडी और सीआरपीएफ पर आरोप लगा रहे थे और ध्यान भटकाकाने तथा पकड़े जाने के बाद के बहाने तैयार कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले से ही लगातार महादेव सट्टा एप के तार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय से जुड़ रहे थे और अब तो स्पष्ट हो गया कि इन सब में भूपेश की सीधी सलिप्तता है। भाजपा की सरकार में हमने जिस छत्तीसगढ़ की पहचान विकास की बनाई उसे 5 साल में ही अपने

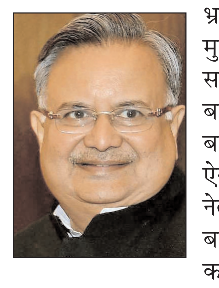

भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जुए सट्टे, श्वष्ठ और ष्ठ्ठ की पहचान में बदल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शायद हिंदुस्तान के पहले ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेसी नेताओं और बड़े अधिकारियों के बच्चों का चयन बड़े पदों पर करवाते हैं और प्रदेश के युवाओं को जुए और सट्टे के दलदल में धकेलकर उनका भविष्य बर्बाद करते हैं उन्हें न छत्तीसगढ़ माफ़ कर सकता है और न ही न्यायालय, यह छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सामने विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के काले कारनामें सामने आ रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता कांग्रेस से सतर्क हो जायेगी और प्रदेश के भविष्य के लिए उचित निर्णय लेगी।

फाफाडीह भाजपा मंडल चुनाव कार्यालय का पुरंदर मिश्रा ने किया उदघाटन

रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा के अंतर्गत भाजपा मंडल फाफाडीह चुनाव कार्यालय का गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के करकमलों से उद्घाटन किया गया। स्थानीय चुनाव प्रचार की गतिविधियां अब भाजपा मंडल फाफाडीह चुनाव कार्यालय से संचालित की जाएंगी। इससे पहले पंडरी में भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा का मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया था। फाफाडीह स्थित पीली बिल्डिंग में भाजपा मंडल फाफाडीह चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्रवासियों ने श्री सोनी और श्री मिश्रा सहित अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। वहीं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कहा कि, यह भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि चुनाव में जीत के हिसाब से रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। चुनावी तैयारी को और सशक्त करने के उद्देश्य से आज से भाजपा मंडल फाफाडीह के लिए पृथक चुनाव कार्यालय खोला गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

बीजेपी सिर्फ बस्तर में लगाती है आग: दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ चुनाव के महासंग्राम में पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है.जिसमें बस्तर की 12 सीटें भी शामिल है.फिलहाल बस्तर में बीजेपी का सूपड़ा साफ है. लिहाजा पार्टी ने पूरी ताकत बस्तर के किले को फतह करने में लगाई है.बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का दौरा बस्तर में हो चुका है.पीएम मोदी समेत अमित शाह का दौरान बस्तर में हो चुका है. इसी कड़ी में कांग्रेस के नेताओं का भी

जमावड़ा बस्तर में लग रहा है.राहुल गांधी आएंगे बस्तर ॉ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया था. वहीं अब बस्तर की जनता को साधने के लिए 04 नवंबर को राहुल गांधी बस्तर दौरे पर रहेंगे. जहां वे जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे. गांधी परिवार के दौरे से होगा फायदा ॉ दौरे से पहले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में गांधी परिवार का शुरू से ही लगाव रहा है. पिछले 2018 के चुनाव में बस्तर पहुंचकर टाटा कंपनी ने जो जमीन अधिग्रहित की थी उसकी वापसी का वादा किये थे.इसके बाद वादा पूरा हुआ.इस समय भी गांधी परिवार से जुड़े लोग बस्तर आ रहे हैं. इसका भी फायदा पिछली तरह के जैसे ही होगा.योगी और राजनाथ के दौरों से नहीं पड़ेगा फर्क ॉ बस्तर की 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खेमे में जाएगी।

रिटर्निंग ऑफिसर से बहस करना पड़ा भारी, 4 लोगों पर जुर्म दर्ज

मुंगेली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बी फार्म भरने वाले नेता मनीष त्रिपाठी और पत्नी सीमा त्रिपाठी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है. रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने चारों पर मामला दर्ज किया है. दरअसल हुआ यूं कि मनीष त्रिपाठी ने जेसीसीजे से बी फार्म भरा था. इसपर जनता कांग्रेस ने उनके खिलाफ कूटरचित बी फार्म भरने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की थी. इसके स्क्रूटनी प्रकिया के

दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मनीष त्रिपाठी का क्क फॉर्म निरस्त कर दिया .जिसके पीछे की वजह बताया गया कि जोगी कांग्रेस की ओर से सागर सिंह बैस को जो क्कफॉर्म जो जारी किया गया था उसमें उल्लेख किया गया था कि पूर्व में मनीष त्रिपाठी को जारी क्क फॉर्म को निरस्त माना जावे का उल्लेख पार्टी द्वारा किया गया था. वहीं फॉर्म रद्द किये जाने पर मनीष त्रिपाठी की रिटर्निंग ऑफिसर से बहस हो गई. मामले की शिकायत में कहा गया है कि मनीष त्रिपाठी ने फॉर्म रद्द किये जाने के बाद हंगामा मचाया. रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मनीष त्रिपाठी और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों पर आईपीसी की धारा 186, 32 के तहत मामला दर्ज किया है. इधर गुरुवार को इस पूरे घटनाक्रम में मनीष त्रिपाठी ने जोगी कांग्रेस की ओर से नामांकन रद्द होने पर उनका निर्दलीय नामांकन को स्टैंड था. उससे भी उन्होंने नाम वापस ले लिया. वहीं बी फार्म को लेकर लगे आरोप पर मनीष त्रिपाठी अब भी कह रहे है कि जोगी कांग्रेस ने मुझे बी फार्म दिया था.

भाजपा ने घोषणा पत्र नहीं कपट पत्र जारी किया है: शुक्ला

रायपुर। पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। यह भूपेश बघेल की उपलब्धि है की धान पर बोनस का विरोध करने वाले धान की कीमत 3100 करने की बात कर रहे है। जो लोग 2100 बोलकर नहीं दिये, 300 बोनस नहीं दिये, जो लोग 15 क्विंटल

नहीं खरीदने का निर्णय लिये थे वे अब 21 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे। यह भूपेश बघेल की उपलब्धि है। घोषणा तो कर रहे लेकिन जनता भरोसा नहीं करेगी। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं जो मोदी, 15 लाख देने का वायदा भूल गये, 2 करोड़ युवाओ को रोजगार देने का वायदा भूल गये, 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा भूल गये, किसानों की आय दुगुनी करने के वायदे तो आज तक पूरे नहीं हुये उनकी क्या गारंटी है। दिग्विजय सिंह की सरकार ने बनाया था, भूपेश सरकार संवार रही। जो हम 5 साल से कर रहे है भाजपा उसको करना चाह रही। वह हमारे पिच पर खेलने को मजबूर हुई।

भाजपा वोट लेने के लिये फिर किसानों को ठगना चाहती। धान की कीमत 3100 रू. करने की घोषणा किया है तो बतायें क्या केन्द्र धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3000 रू. करेगी। क्योकि मोदी जी तो धान की कीमत समर्थन मूल्य से 1 रू. भी ज्यादा देने के विरोधी है।

जन सरोकार भाजपा की प्राथमिकता में कहीं नहीं हैं: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का असल चेहरा और एक सूत्रीय एजेंडा उजागर हो गया है। जन सरोकार नहीं अडानी का मुनाफे पर ही भाजपा का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी बस्तर आकर झूठ बोले की एनएमडीसी का नगरनार प्लांट नहीं बेचा जायेगा। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार के दीपम की सरकारी वेबसाइट पर विनिवेशीकरण

के लिये सेल लगाकर बेचे जाने वाले सरकारी कंपनियों की सूची में एनएमडीसी नगरनार प्लांट आज भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के संसाधन, छत्तीसगढ़ के माइंस, छत्तीसगढ़ के सीमेंट उद्योग, स्टील प्लांट, पॉवर प्लांट पर अडानी का एकाधिकार स्थापित करने के लिए भाजपाई छत्तीसगढ़ में सत्ता हथियाना चाहते हैं। भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता सामाजिक न्याय के साथ ही छत्तीसगढ़िया जनता की समृद्धि है। भूपेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, मोदी सरकार ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का। भूपेश सरकार ने 1 लाख 75 हजार करोड़ की राहत और सब्सिडी छत्तीसगढ़ के अलग-अलग वर्गों के हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे तौर पर डालने का काम किया है। मोदी सरकार ने हर तरह की राहत और रबड़ी केवल चंद पूंजीपति मित्रों को दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 15 साल रमन सिंह के कुशासन में छत्तीसगढ़ मोदी के पूंजीपति मित्रों का चारागाह बनाकर रखा गया था। जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी।

भूपेश बताएं असीम दास से मिले 508 करोड़ कहां है: गुप्ता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार नाथ गुप्ता ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस रिलीज में यह सामने आ गया है कि असीम दास से पूछताछ में मिले तथ्यों की जांच के दौरान तथ्य सामने आए हैं कि महादेव एप प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

बताएं कि यह 508 करोड़ रुपए उन्होंने कहां रखें हैं और इनका चुनाव में क्या इस्तेमाल हो रहा है। पूर्व में भी एक एएसआई गिरफ्तार हो चुका है अब फिर एक सिपाही गिरफ्तार हुआ है। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस भूपेश बघेल के एजेंट के तौर पर इस गोरख धंधे में शामिल है? अब जांच सीआरपीएफ के जवानों की होनी चाहिए या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुरक्षा बलों पर लगाए आरोप पर अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कल ईडी द्वारा की गई कार्यवाही और जप्त रकम पर शंका जाहिर करते हुए कहा कि यह पैसा बहुचर्चित महादेव सट्टा एप का हो सकता हैं और हवाला के जरिए छत्तीसगढ़ भेजा गया होगा और इसका उपयोग चुनाव में किया जा सकता है इस पर भी जांच होनी चाहिए।श्री गुप्ता ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि उनके बक्सों में पैसा भरकर लाया जा रहा है।

घोषणा पत्र पर रमन : पूर्व सीएम ने कहा,

'किसान 2500 में बेच लें अपना धान, सरकार बनने पर हम देंगे बकाया छह सौ रुपये'

रायपुर. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की. उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसान अभी धान बेच सकते हैं, प्रदेश में जो समर्थन मूल्य हैं 2500 में बेच सकते हैं. बाकी के पैसे 600 रुपये हमारी सरकार आने के बाद देंगे. कृषि उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, ये किसानों की मांग थी. समर्थन मूल्य 3100 रुपये दिया जाएगा. बोनस की राशि साल भर की एक मुश्त दी जाएगी.

रमन सिंह ने कहा कि आज हमने ऐतिहासिक संकल्प पत्र जारी किया है. सुनहरा भविष्य पीएम मोदी की गारंटी है. हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प अटल है, हर वर्ग की चर्चा की गई है, किसान के हित में फैसले लिए हैं. रेडी टू इट का काम स्व-सहायता समूह की महिलाओं से कांग्रेस ने छिना था, उसे हम वापस करेंगे. मजदूर किसान को 10 हजार सलाना मदद उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा. स्नातकोत्तर च्त्र से क्क्र बेटियों को निःशुल्क शिक्षा भाजपा सरकार देगी.

देवगुड़ी के निर्माण की राशि 1 लाख थी, बढ़ाकर 5 लाख निर्माण में खर्च किया जाएगा. छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रैवल भत्ता दिया जाएगा. राज्य सरकार के कर्मचारी को केंद्र के बराबर ष्ठ प्रदान करेंगे.

भूपेश बघेल को भी बोनस देंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे- रमन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा दे तो रहे हैं भूपेश बघेल, 3100 रुपये दे दिए तो भूपेश को प्रसन्न होना चाहिए. केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद देना चहिए. भूपेश भी किसान हैं उनको भी देंगे उनको नहीं छोड़ेंगे. 21 क्विंटल धान बेचेंगे, बाहर से धान बेचने वाले पर हम सख्त होंगे. हमने 50 हजार कर्मचारियों को नियमित किया था. हमारी सरकार आएगी तो फिर नियमित करेंगे. मुख्यमंत्री का बयान चंदखुरी हो आइये बाद में सबको राम लला के दर्शन कराने ले जाना पर रमन सिंह ने कहा कि चंदखुरी हर साल जाते हैं, इस बार जाएंगे तो उनके घर जाएंगे उन्हें भी बोलेंगे चलो हमारे साथ कितने बार जा चुके हैं.

शराबबंदी को लेकर रमन सिंह ने कहा कि हमने शराबबंदी लागू करने का विरोध नहीं किया, पूर्व में हमने शराबबंदी कर दिया था, महिला कमांडो को हमने अधिकार दिया था कि वो छोटे गांव को शराब से मुक्त करें।

शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य में सभी सहयोग दें: प्रेक्षक जोथी

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा धरसीवा के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्रीमती अमरीथा जोथी आज धरसीवा क्षेत्र के प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वे चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों व दीपावली त्यौहार व मिलन समारोहों का उपयोग न करें। आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी

को यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लांच किए गए सी-विजिल एप में उसकी शिकायत कर सकता है या मैनुअली अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर सकता है। चुनाव के सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी एक-एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं जो अभ्यर्थी के स्थान पर कार्य कर सकेंगे। व्यय अभिकर्ता के रूप में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति अभ्यर्थी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी निर्वाचन के लिए किए जा रहे अपने खर्चों के लेखों को प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज कर समुचित रिकार्ड रखेंगे। व्यय प्रेक्षक यदि जरूरी समझेंगे तो वे अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर को तलब कर उसका परीक्षण कर सकेंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.